



संक्षिप्त समाचार

सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। ईडी की टीम ने सुबह से रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली समेत करीब 10 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित तौर पर काले धन के इस्तेमाल से जुड़े मामले में की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े परिसरों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। आजम खान के खिलाफ दर्ज कई दर्जन मामलों की जानकारी ईडी के साथ साझा किए जाने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है। यूनिवर्सिटी में कथित अनियमितताओं के चलते इसकी 40 में से 38 इमारतों को गिराए जाने का खतरा पैदा हो गया था। हालांकि, इस मामले में अदालत ने फिलहाल रोक लगा रखी है।

कुर्सी नहीं, तो ट्रेन भी आगे नहीं जाएगी' गार्ड की जिद से थमे वैशाली एक्सप्रेस के पहिए

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला और अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां एक छोटी सी मांग पूरी न होने पर एक महत्वपूर्ण और वीआईपी ट्रेन के पहिए अचानक थम गए। नई दिल्ली से ललितगाम जा रही वैशाली एक्सप्रेस के गार्ड की जब बैठने के लिए सही कुर्सी नहीं मिली, तो वह इस करार नाराज हुआ कि उसने ट्रेन को आगे ले जाने से ही साफ इनकार कर दिया। गार्ड को इस जिद से रेलवे अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए और स्टेशन पर भारी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। काफी मान-मनौवल्ल के बाद जाकर ट्रेन आगे के सफर के लिए रवाना हो सकी। जानकारी के मुताबिक, 18 अगस्त की सुबह नई दिल्ली-ललितगाम वैशाली एक्सप्रेस (15S66) सुबह करीब 9:47 बजे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची थी।

दविंदर बंबीहा गैंग के तीन वांटेड सदस्य मलेशिया से डिपोर्ट

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस को अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। काउंटर इंटेलिजेंस विंग के ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रेकिंग एंड एक्सट्रैडिशन सेल (ओएफटीईसी) ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से दविंदर बंबीहा गैंग से जुड़े तीन वांटेड सदस्यों को मलेशिया से डिपोर्ट करवाया है। यह जानकारी पंजाब डीजीपी की ओर से एक्स पर पोस्ट कर दी गई। पंजाब पुलिस ने बताया कि इन तीनों लोगों पर हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने और लुभियाना में एक सुनियोजित हैंड-ग्रेनेड धमाके (जिसके तार पाकिस्तान की आईएसएआई से जुड़े थे) जैसे कई मामलों में आरोप हैं। आरोपी जसप्रीत सिंह उर्फ जस बेहबल, अजय सिंह और पवनदीप सिंह।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ली तलाशी

कांग्रेस के पूर्व नेता रामगोपाल अग्रवाल के घर ईडी की रेड...

रायपुर/ समय दर्शन

छत्तीसगढ़ के धमतरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार सुबह कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता रामगोपाल अग्रवाल के निर्माण में कथित तौर पर काले धन के इस्तेमाल से जुड़े मामले में की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े परिसरों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। आजम खान के खिलाफ दर्ज कई दर्जन मामलों की जानकारी ईडी के साथ साझा किए जाने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है। यूनिवर्सिटी में कथित अनियमितताओं के चलते इसकी 40 में से 38 इमारतों को गिराए जाने का खतरा पैदा हो गया था। हालांकि, इस मामले में अदालत ने फिलहाल रोक लगा रखी है।



दुर्ग में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दो रियल एस्टेट कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी.....

दुर्ग। दुर्ग-भिलाई में गुरुवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े सजल जैन और विश्वास गुप्ता के ठिकानों पर पहुंचकर जांच शुरू की है। दोनों कारोबारियों के ठिकानों को कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के यहां हुई ईडी की कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, दुर्ग के गांधी चोक स्थित जय आनंद परिसर, जैन गली, डॉक्टर ताम्रकार के समीप सजल जैन से जुड़े परिसर समेत कुछ अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। यहां जांच एजेंसी द्वारा दस्तावेजों और कारोबारी लेन-देन से जुड़े रिकॉर्डों की जांच किए जाने की जानकारी है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई सजल जैन और विश्वास गुप्ता से जुड़े कार्यालय एवं आवासीय परिसरों पर केंद्रित है। सजल जैन का संबंध रिद्धि-सिद्धि बिल्डर्स से बताया जा रहा है, जबकि विश्वास गुप्ता भी इस बिल्डर समूह से जुड़े पार्टनर रहे हैं। इसके अलावा दुर्ग के शनिचरी बाजार स्थित श्रीराम हार्डवेयर में भी रियल एस्टेट कारोबारी विश्वास गुप्ता से जुड़े ठिकाने पर ईडी की टीम द्वारा कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। सुबह से ही जांच एजेंसी की टीम अलग-अलग परिसरों में दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्डों को खंगाल रही है। फिलहाल ईडी की इस कार्रवाई को लेकर एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। यह कार्रवाई किस मामले में और किन दस्तावेजों अथवा वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए की जा रही है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल से जुड़े परिसरों में चल रही ईडी की जांच से संबंधित हो सकती है। हालांकि, इस संबंध की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

की गई। एजेंसी ने जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह भी दावा किया है कि अपराध से अर्जित नकद राशि का एक बड़ा हिस्सा रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाया गया। ईडी के मुताबिक, उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे अग्रवाल तक यह नकदी सिंडिकेट के कथित हैंडलरों के माध्यम से पहुंचाई गई। ईडी के अनुसार पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए उन लोगों के बयानों में भी नकदी

रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए जाने की जानकारी सामने आई है, जिन्होंने कथित तौर पर रकम को संभाला और स्थानांतरित किया था। धमतरी स्थित निवास पर जारी मौजूदा कार्रवाई में ईडी की टीम किन दस्तावेजों अथवा रिकॉर्डों को जांच के दायरे में ले रही है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ईडी के अनुसार कथित शराब घोटाले को 2019 से 2022 के बीच एक 'सिंडिकेट' ने अंजाम दिया था।

धमाल के राइट्स बेचने के नाम पर 1.50 करोड़ की ठगी

मुंबई। मुंबई के फिल्म उद्योग से धोखाधड़ी और जालसाजी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय कॉमेडी फिल्मों में से एक धमाल के डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल और कॉपीराइट्स बेचने के नाम पर एक नामी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ 1.50 करोड़ की बड़ी ठगी का खुलासा हुआ है। इस मामले में अंबोली पुलिस ने 17 अगस्त 2026 को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अशोक नवल कुमार ठाकरिया और दिग्गज निर्देशक इंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई अंधेरी पश्चिम स्थित प्रमुख फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ग्रेड मास्टर के मालिक विकास बलदेवराज साहनी द्वारा दर्ज कराई गई।

वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले से भड़के गृहमंत्री

1937 की गलती दोहरा रही पार्टी देश के बंटवारे की...अमित शाह

नई दिल्ली/ एजेंसी

कांग्रेस कार्य समिति के 'वंदे मातरम' के केवल दो पैराग्राफगाने के पुराने फैसले को दोहराने के बाद देशभर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसका समर्थन किया है, वहीं भाजपा ने इसे शहीदों का अपमान करार दिया है। कांग्रेस के इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोला है। शाह ने अपने चेन्नई दौर के बीच कांग्रेस के इस फैसले की निंदा की। तमिलनाडु के चेंगलपट्टु वंदे मातरम पर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी (कांग्रेस वर्किंग कमेटी) के प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कल कांग्रेस वर्किंग



कमिटी ने देश-विरोधी फैसला लिया। 1937 के अपने प्रस्ताव को मानते हुए, कांग्रेस ने वंदे मातरम के सिर्फ दो पद गाने का फैसला किया। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि 1937 में मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम को बांटकर कांग्रेस ने देश के बंटवारे की नींव रखी थी। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय एकता

को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की उस गलती को सुधारा है और इसे कानूनी आधार भी दिया है। अमित शाह ने आगे कहा, कांग्रेस का यह फैसला उसकी तुष्टिकरण की नीति को साबित करता है। उन्होंने न सिर्फ बंकिम बाबू की इस रचना का अपमान किया है, बल्कि उन लाखों लोगों का भी अपमान किया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी। आज कांग्रेस पार्टी अपने 1937 के प्रस्ताव को तो लागू कर रही है, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून को नकार रही है। अमित शाह ने हैरानी जताते हुए कहा, मुझे हैरानी है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है।

पीएम मोदी का शासन आखिरी दौर में है

उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है-राहुल गांधी..

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक अंत हो चुका है और उनका शासन अब अंतिम दौर में है। राहुल गांधी के मुताबिक, मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि राहुल गांधी ने बैठक में कहा, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक अंत हो चुका है। उनका वक्त खत्म हो गया है। मोदी का शासन आखिरी दौर में है। उनके



उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को पूरी तरह बैकफुट पर बताया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सरकार के खिलाफ और आक्रामक तरीके से मोर्चा लेने की अपील की।

तिहाड़ में काट रहे थे उम्रकैद की सजा

1984 सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार का हुआ निधन.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

पूर्व सांसद और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता सज्जन कुमार का निधन हो गया है। उन्हें दिल्ली के सफरदर्जन अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। निधन की खबर मिलते ही दिल्ली में कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार के बेटे जग प्रवेश कुमार सफरदर्जन अस्पताल पहुंचे। बता दें, कि सज्जन कुमार पिछले 7 सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे और सजा काट रहे थे। 81 की उम्र में गुरुवार 20 अगस्त को उनका निधन हो गया। जब उन्हें अस्पताल



लाया गया तो पता चला कि काफी पहले ही उनका निधन हो गया था। अप्रैल 2026 में उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सज्जन कुमार 1984 के सिख-विरोधी दंगों

से जुड़े दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। दिल्ली कैंट के पालम कॉलोनी इलाके में पांच सिखों की हत्या के बाद एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। सज्जन कुमार को इस मामले में दोषी पाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सितंबर 2023 में, राउज एक्वेय कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के सुल्तानपुरी में तीन सिखों की हत्या से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया। दंगों से जुड़ी सीबीआई की मुख्य गवाह चाम कौर ने आरोप लगाया था कि सज्जन भीड़ को उकसा रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला-प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोपों की होगी जांच

आरोपों की जांच करेगी 5 सदस्यीय कमेटी,पूर्वजज रेड्डी होंगे अध्यक्ष

नई दिल्ली/ एजेंसी

नीट पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों पर लगे कथित बल प्रयोग के आरोपों की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी गठित की है। कमेटी दिल्ली के जंतर-मंतर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी को पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अलावा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि शंकर

झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शल्लिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रूचि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी डॉ. एलआर बिश्नोई कमेटी के सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ से जुड़े आरोपों की प्राथमिकता से जांच करने को कहा है। कमेटी यह भी देखेगी कि प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोट पहुंचाने या अन्य नुकसान के जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें सुरक्षा बलों की कार्रवाई किस स्तर के आदेश या चेन ऑफ कमांड पर तहत हुई थी। कमेटी के जांच के दायरे में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर किए गए अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप भी शामिल हैं। इनमें लाठीचार्ज, आंसू



गैस, इलेक्ट्रिक बैटन और पेलेट गन जैसे साधनों के इस्तेमाल की परिस्थितियों की जांच की जाएगी। पैनल यह भी जांच करेगा कि प्रदर्शनकारियों को बल प्रयोग से पहले पर्याप्त चेतावनी दी गई थी या नहीं और इस्तेमाल किया गया बल परिस्थितियों के अनुपात में था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी

कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है और केवल आंदोलन करने के आधार पर पुलिस कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने प्रदर्शनों से निपटने के लिए देशभर में एक समान प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। कमेटी यह भी देखेगी कि पंप-एक्शन

या प्रोजेक्टाइल-एक्शन गन से दागे जाने वाले मेटैलिक काइनेटिक प्रोजेक्टाइल या पेलेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा चुका है और दिल्ली पुलिस से इसके इस्तेमाल से संबंधित एसओपी रिकॉर्ड पर रखने को कहा गया था। जांच का एक अहम पहलू यह भी होगा कि प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ बल प्रयोग के दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने निर्धारित यूनिफॉर्म और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली नेमप्लेट पहनी थी या नहीं। कमेटी यह भी देखेगी कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई के दौरान लागू कानूनों, नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया या नहीं।

जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं नहीं होगी रद्द, हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले पर लगाई रोक

झारखंड में छुजेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद में अब एक नया टि्वस्ट आया है। हाल ही में छान आंदोलन और परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवालों के बाद राज्य की सोरेन सरकार ने कुछ परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया था। सोरेन सरकार का तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर छात्रों में संदेह पैदा हुए हैं, इसलिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला जरूरी है। झारखंड सरकार के इस आदेश के खिलाफ कई नवनिर्भुक्त अधिकारियों और अभ्यर्थियों द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई थी।

स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख निर्माण में धमतरी जिला प्रदेश में अत्तल

धमतरी। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को उनकी भूमि पर स्वामित्व का वैधानिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना का निर्माण में प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत राजस्व ग्रामीण आबादी प्रचलित एवं सुरक्षित भूमि में निवासरत पात्र परिवारों को उनके अधिकारों का अभिलेखीकरण कर अधिकार अभिलेख वितरित किए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण अधिकार अभिलेख निर्माण एवं वितरण के क्षेत्र में धमतरी जिला प्रदेश में अग्रणी रहा है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले के 501 राजस्व ग्रामों में ड्रोन फ्लाई कराराया गया है। ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार की कार्यान्वयन एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त मानचित्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया। इस प्रक्रिया में मैदानी



स्तर पर स्थल सत्यापन, पात्र परिवारों की पहचान तथा आबादी भूमि से संबंधित अभिलेखों का परीक्षा किया गया, ताकि तैयार किए जा रहे अधिकार अभिलेख शुद्ध, प्रमाणिक एवं त्रुटिरहित हों। योजना के तहत अब तक 312 ग्रामों के अभिलेख पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं तथा 50 हजार से अधिक अधिकार अभिलेखों का वितरण पात्र हितग्राहियों को किया गया है। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी आबादी

भूमि के संबंध में स्पष्ट एवं वैधानिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अधिकार अभिलेख मिलने से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण उपलब्ध होने के साथ ही भविष्य में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का लाभ लेने, संपत्ति संबंधी लेन-देन तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में सुविधा प्राप्त होगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का विधिवत अधिकार प्रदान

करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि जिले में योजना के क्रियान्वयन में अभिलेखों की शुद्धता, पारदर्शिता और समयबद्धता को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष ग्रामों में भी आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर पात्र परिवारों को अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने तथा किसी भी स्तर पर त्रुटि की गुंजाइश नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाने, भूमि अभिलेखों को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने तथा ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के माध्यम से आर्थिक अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है। जिले में योजना के तहत की जा रही कार्यवाही ग्रामीण विकास एवं सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भगवान भोलेनाथ की भक्ति में अपार शक्ति है : रंजना साहू

धमतरी। बृद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बोल बम कांविरिया संघ द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं धमतरी पूर्व विधायक रंजना डोपेद्र साहू शामिल हुईं। उन्होंने कथा वाचक पंडित हरिशरण वैष्णव के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा का श्रवण किया तथा व्यासपीठ को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर रंजना साहू ने उपस्थित श्रद्धालुओं को पावन श्रावण मास की शुभकामनाएं देते हुए भगवान भोलेनाथ से समस्त क्षेत्रवासियों के सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। अपने उद्घोषन में रंजना साहू ने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और भक्ति का पावन पर्व



है। शिव महापुराण कथा हमें धर्म, सत्य, सेवा, संस्कार और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में अपार शक्ति है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक शांति का संचार होता

है। ऐसे धार्मिक आयोजनों से हमारी सनातन संस्कृति और संस्कारों को मजबूती मिलती है तथा समाज में आपसी भाईचारा और एकता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि बोल बम कांविरिया संघ द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का सुंदर

अवसर है। कथा श्रवण के साथ हमें भगवान शिव के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का सकल्य लेना चाहिए। महादेव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और प्रत्येक परिवार में सुख,समृद्धि एवं खुशहाली का वास हो। शिव महापुराण कथा के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सज्जा रह। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण कर भगवान शिव की आराधना की। इस अवसर पर एल्डरमेन सीमा चौबे, एल्डरमेन रितिका यादव, पूर्व जनपद सदस्य जागेश्वरी साहू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहे। आयोजन में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए और क्षेत्र की सुख,समृद्धि की कामना की।

बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक और सार्थक कदम



सरायपाली। सरायपाली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलौदा के स्कूल प्रांगण में शासन की महत्वाकांक्षी सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह उत्साह पूर्वक किया गया। इस योजना का उद्देश्य हमारी बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यालय आने-जाने की कठिनाइयों को दूर करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर, सुरक्षित एवं सशक्त बनाना है। साइकिल का यह उधार बेटियों के सपनों को गति देने और उनकी शिक्षा की राह को और सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम में जिला पंचायत सभापति एवं भाजपा जिला मंत्री कुमारी भास्कर , जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रकाशचंद्र पटेल , मंडल अध्यक्ष नीलांबर तांडी , जनपद पंचायत सदस्य पद्मनी भोई , शाला प्रबंध समिति के अध्यक्ष सारथी नाग , उग्र सरपंच सरोज सेठ , सलडीह सरपंच दयानन्द पटेल जी,शाला प्रबंधन समिति सदस्य स्तं लाल सोना , उमेश श्रीवास , विद्यालय के प्राचार्य अरुण कुमार सतपथी , धनेश्वर भास्कर , शिक्षकगण, पालकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

जोधपुर में 23 अगस्त को धूमधाम से मनाई जाएगी गुरु बालक दास जयंती

धमतरी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परम पुण्य गुरु घासीदास बाबा के द्वितीय पुत्र, शूरवीर, महान प्रतापी एवं अमर बलिदानी राजा गुरु बालक दास की जयंती समारोह का भव्य आयोजन 23 अगस्त 2026 को जोधापुर धमतरी में अत्यंत उत्साह एवं गरिमा के साथ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन सतनामी समाज कल्याण समिति, जोधापुर द्वारा किया जा रहा है। समिति के सदाधिकारियों ने बताया कि राजा गुरु बालक दास के शौर्य, त्याग और सामाजिक समरसता के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने तथा नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से विविध कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है। गुरु बालक दास वेशभूषा प्रतियोगिता-राजा गुरु बालक दास के स्वरूप को शोधार्थ प्रस्तुति। पारंपरिक पंथी नृत्य-प्रसिद्ध पंथी दलों द्वारा गुरु महिमा एवं शौर्यगाथा पर आधारित भव्य सांस्कृतिक



प्रस्तुति। रंगोली प्रतियोगिता-सामाजिक संदेश के साथ संस्कृति पर आधारित रंगोली स्पर्धा। खेलकूद प्रतियोगिताएं-बच्चों एवं युवाओं के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः जैत्रधाम पूजा.अर्चना के साथ होगा। इसके पश्चात दोपहर से विविध प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शुरू होंगी। शाम को विजेताओं का सम्मान एवं पुरस्कार वितरण किया जाएगा। सतनामी समाज कल्याण समिति, जोधापुर धमतरी ने समस्त समाज जन, क्षेत्रवासियों एवं श्रद्धालुओं से इस पावन अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने एवं इसे सफल बनाने की सहर्ष अपील की है।

दिव्य धाम में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया

धमतरी। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्त्वबोधन में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडारोहण और तिरंगा यात्रा का गरिमामय आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी सरिता बहन ने झंडा रोहन पश्चात स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारत माता के महान सपुतों जिन्होंने अपनी

कुर्बानी देकर देश को आजाद कराया उनका जीवन अनुशासन मर्यादा देश प्रेम तथा जन कल्याण की भावना आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। अपने जीवन में स्वतंत्रता संग्राम सेमिनारियों, शहीदों और देश के स्वर्णिम इतिहास के पृष्ठों में अंकित गाथा हम सबको ऊर्जा प्रदान करने वाला है। हमें अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र

बनाने के लिए देश की समृद्धि में यथोचित योगदान देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अभी समय है कि हमारा देश नशा मुक्त राष्ट्र बने ताकि भारत अपनी सोने की चिड़िया जैसा स्वरूप पुनः प्राप्त कर सके। कार्यक्रम का संचालन कामिनी कौशिक ने किया। तत्पश्चात देश भक्ति पूर्ण वातावरण में स्लोगन और नारे बोलते हुए आकर्षक

तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें नगर पालिक निगम धमतरी के महापौर जगदीश रामू रोहरा एवं नरेंद्र पाण्डे एवं सभापति प्रधानमंत्री पुनर्वासि नगरपालिक धमतरी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ईश्वरीय परिवार से ब्रह्माकुमारी बहनें एवं सैकड़ों भाई-बहनों ने अपना अमूल्य योगदान दिया।

संबलपुर,बोडरा,बलियारा.भोथली.छाती मार्ग के चौड़ीकरण को जल्द मिलेगी मंजूरी : रामू रोहरा

धमतरी। जिले के ग्रामीण अंचल को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। संबलपुर, बोडरा, बलियारा, भोथली एवं छाती मार्ग के चौड़ीकरण की वर्षों पुरानी मांग अब जल्द पूरी होने की उम्मीद है। लंबे समय से ग्रामीण इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। मार्ग पर लगातार बढ़ते आवागमन और वाहनों की संख्या के कारण सड़क की चौड़ाई बढ़ाना क्षेत्र की प्रमुख जरूरत बन गई है। ग्रामीणों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम धमतरी के महापौर रामू रोहरा



ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव, प्रधारी मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद रूपकुमारी चौधरी से मार्ग चौड़ीकरण की

स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। महापौर ने सरकार के समक्ष क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, ग्रामीणों की परेशानी और मार्ग के महत्व को रखते हुए शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की। महापौर के अनुसार शासन स्तर पर इस प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक रुख है और जल्द ही मार्ग चौड़ीकरण के लिए स्वीकृति मिलने की संभावना है। संबलपुर से बोडरा, बलियारा, भोथली होते हुए छाती तक जाने वाला मार्ग आसपास के गांवों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान,

विद्यार्थी, कर्मचारी और अन्य लोग आवागमन करते हैं। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण कई स्थानों पर वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। विशेषकर बड़े वाहनों की आवाजाही के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। मार्ग के चौड़ीकरण से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था भी बेहतर होगी। किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी और विद्यार्थियों तथा नौकरिपेशा लोगों को भी आने-जाने में राहत मिलेगी।

महावीर इंटरनेशनल द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 22 को

धमतरी। समाजसेवी संस्था महावीर इंटरनेशनल द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 22 अगस्त शनिवार को किया जा रहा है जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हड्डी रोग, तंत्रिका रोग और हृदय रोग के अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों की निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया जाएगा। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में छत्तीसगढ़ के मशहूर अस्पताल आईएलएस हॉस्पिटल रायपुर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ कुणाल ओस्तवाल, न्यूरोसर्जन डॉ अमित जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ अभिषेक त्रिपाठी और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ शिखा बुधवानी सेवाएं देगी। डॉक्टर बुधवानी अनुभवी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, जो हार्मोन से संबंधित बीमारियों जैसे शुगर एवं शरिर में विभिन्न हार्मोन के अनियमित स्त्राव संबंधी जटिलताओं की विशेषज्ञ है।

शिविर में आधुनिक मशीनों द्वारा बीपीए शुगर, लिपिड प्रोफाइल, बीएमआई, बीएमडी और न्यूरोपैथी टेस्ट जैसे परीक्षण निःशुल्क किए जाएंगे। शिविर के प्रायोजक राजेश प्रजापति हैं। शिविर 22 अगस्त शनिवार को सिहावा चौक के पास नवीन स्थानक भवन में प्रातः 9 बजे से 2 तक होगा। महावीर इंटरनेशनल ने सभी नागरिकों से शिविर का अधिकाधिक लाभ उठाने का अनुरोध किया है।

चंदा देवी तिवारी अस्पताल में डॉ. वेद प्रकाश वर्मा ने शुरु की नियमित सेवाएं

बलौदाबाजार। पहले दिन 53 मरीजों का किया परीक्षण, स्थानीय नागरिकों ने किया अभिनंदन चंदा देवी तिवारी अस्पताल में अब से प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. वेद प्रकाश वर्मा ने अपनी नियमित चिकित्सा सेवाएं देना शुरू कर दिया है। सेवा के पहले ही दिन डॉ. वेद प्रकाश वर्मा ने 53 मरीजों का परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श दिया। डॉ. वेद प्रकाश वर्मा की नियमित सेवाएं शुरू होने पर क्षेत्र के स्थानीय गणमान्य नागरिकों एवं आमजनों ने उनका अभिनंदन एवं स्वागत किया। इस अवसर पर नागरिकों ने जिले में हृदय रोगियों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की पहल के लिए चंदा देवी तिवारी अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. नितिन तिवारी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस



अवसर पर अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. नितिन तिवारी ने कहा कि पिछले लगभग 10 वर्षों में यह देखने में आया है कि जिले के हृदय रोगियों को हार्ट अटैक जैसी आपात स्थिति में उपचार के लिए रायपुर अथवा बिलासपुर का रुख करना पड़ता था।

हृावर में आवश्यक उपचार नहीं मिल पाता था, जिसके चलते कुछ मरीजों की जान तक चली जाती थी। उन्होंने कहा कि इसी गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए चंदा देवी तिवारी अस्पताल में कैथ लेब की शुरुआत करने तथा विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में पहल की गई है। इसका उद्देश्य जिले एवं आसपास के

क्षेत्रों के हृदय रोगियों को समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा एवं आवश्यक उपचार उपलब्ध कराना है, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को उपचार के लिए दूर-दराज के शहरों में जाने की आवश्यकता कम हो और बहुमूल्य समय बचाया जा सके। डॉ. नितिन तिवारी ने कहा कि अस्पताल में कार्डियक सेवाओं के विस्तार से जिले के लोगों को स्थानीय स्तर पर आधुनिक हृदय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा हार्ट अटैक के मरीजों के लिए समय पर उपचार की संभावना और बेहतर होगी। चंदा देवी तिवारी अस्पताल प्रबंधन ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि हृदय संबंधी किसी भी समस्या अथवा आपात स्थिति में समय पर चिकित्सकीय परामर्श लें और आवश्यक उपचार में देरी न करें।

कीटनाशक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण, 3 विक्रेताओं को नोटिस

बलौदाबाजार। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2026 अंतर्गत वर्तमान कृषि कार्य को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशक दवाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य जिले के कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से कीटनाशक विक्रय केंद्रों में दंडित देकर सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 3 विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया। विकासखंड पलारी के निरीक्षक सुचिन कुमार वर्मा ने ग्राम संंडी में संचालित महेंद्र कृषि सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्र में कैश मेमो तथा स्रोत प्रमाण पत्र का उचित संंधारण नहीं पाए जाने के कारण विक्रेता को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। ग्राम कोदवा में संचालित कोटिहट कृषि सेवा केंद्र के औचक निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्र में कैश मेमो का उचित संंधारण नहीं पाया गया जिस



है। ग्राम संंडी के ही भगत कृषि सेवा केंद्र के निरीक्षण के दौरान स्रोत प्रमाण पत्र का उचित संंधारण नहीं पाए जाने के कारण विक्रेता को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। ग्राम कोदवा में संचालित कोटिहट कृषि सेवा केंद्र के औचक निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्र में कैश मेमो का उचित संंधारण नहीं पाया गया जिस

कारण उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। विकासखंड सिमगा के कीटनाशक निरीक्षक आँलिव मेरो कुबूर ने किसान कृषि केंद्र, दामाखेड़ा का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विकासखंड कसडील के कीटनाशक निरीक्षक धनेश्वर साय ने ग्राम कटगी में संचालित साहजित कृषि सेवा केंद्र

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा,अवमानक गुड़ पर 50 हजार जुर्माना

बलौदाबाजार। आगामी विभिन्न पर्वों एवं बरसात के मौसम को दृष्टिगत दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों को सुरक्षित, शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं मानक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में सात दिवसीय सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान चरने खाबो-बने रहिये 2.0 पूरे जिले में पंचसंचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान हेतल,ढाबो एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जा रही है।पूर्व जांच के दौरान ज्ञानचंद एंड सस,



सदर बाजार भयाटपारा से गुड़ का नमूना जाँच हेतु लिया गया था जो जाँच में अवमानक पाए जाने पर अतिरिक्त

जिला दंडाधिकारी द्वारा सम्बंधित फर्म पर 50000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। मंगलवार को लिटल

चौड़ीकरण को जल्द मिलेगी मंजूरी : रामू रोहरा

विकास की रफ्तार को मिलेगी गति
महापौर रामू रोहरा ने कहा कि सड़क केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। बेहतर सड़क सुविधा से गांवों में व्यापारिक गतिविधियों, कृषि परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। संबलपुर,बोडरा,बलियारा,भोथली.छाती मार्ग के चौड़ीकरण से इन क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग को शासन के समक्ष प्रथमिकता से रखना गया है। मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री से चर्चा के बाद उम्मीद है कि जल्द ही इस महत्वपूर्ण मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण की प्री या आगे बढ़ेगी। महापौर ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और मांगों को शासन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले के विकास के लिए सड़क, पानी, बिजली सहित मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ना भी इसी विकास प्री या का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि संबलपुर, बोडरा, बलियारा, भोथली और छाती क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की भावनाओं और आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के समक्ष यह विषय रखा है। शासन से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद अब ग्रामीणों को जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

जनहित के कार्यों को प्राथमिकता
महापौर रामू रोहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। धमतरी जिले की जरूरतों को भी शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में सड़क एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। महापौर ने मार्ग चौड़ीकरण की मांग पर सकारात्मक पलट के लिए मुख्यमंत्री किष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा एवं सांसद रूप कुमारी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों के लिए वे आगे भी शासन के समक्ष लगातार मांग रखते रहेंगे। उन्होंने विधास जताया कि संबलपुर, बोडरा, बलियारा,भोथली.छाती मार्ग के चौड़ीकरण की स्वीकृति जल्द प्राप्त होगी। स्वीकृति के बाद वर्षों से इस मांग को लेकर प्रयास कर रहे ग्रामीणों का इंतजार खत्म होगा और क्षेत्र में सड़क सुविधा का विस्तार होने से विकास की नई राह खुलेगी।

खेतों से समिति तक पहुंचे कलेक्टर, गिरदावरी की जांच के साथ एग्रीस्टैक पंजीयन का लिया जायजा

बीजापुर। खरीफ वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में चल रहे गिरदावरी एवं ई-गिरदावरी कार्य की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर विश्वदीप ने तहसील बीजापुर के ग्राम धनोरा पहुंचकर मैदानी गिरदावरी कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खेतों में पहुंचकर मौके पर बोई गई फसल एवं वास्तविक रकबे का जायजा लिया तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज जानकारी से उसका मिलान किया। कलेक्टर ने संबंधित मैदानी अमले को निर्देशित किया कि गिरदावरी कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गिरदावरी में दर्ज फसल एवं रकबे की जानकारी समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपजर्जन, ग्राइस स्पेर्ट स्कीम, आरबीसी 6(4), प्रधानमंत्री फ सल बीमा योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक खेत की वास्तविक स्थिति के आधार पर सही प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। विभागीय निर्देशों के अनुसार गिरदावरी के



मैदानी एवं रैंडम सत्यापन के लिए अलग-अलग स्तर पर प्रतिशत निर्धारित किया गया है। पटवारी द्वारा ग्राम स्तर पर 100 प्रतिशत, राजस्व निरीक्षक द्वारा 25 प्रतिशत, कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा 25 प्रतिशत, नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा 10 प्रतिशत तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा 5 प्रतिशत गिरदावरी का सत्यापन किया जाएगा।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्धारित प्रतिशत के अनुसार सत्यापन अनिवार्य रूप से पूरा करने तथा 'भुईयां' सॉफ्टवेयर में वास्तविक फसल एवं रकबे की त्रुटिरहित प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे और मौके पर पाए गए वास्तविक रकबे में अंतर मिलने पर संबंधित मैदानी अमले एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों की जवाबदेही तय

कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिन ग्रामों में ई-गिरदावरी (डीसीएस) प्रस्तावित है, वहां पुनः मैनुअल गिरदावरी की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं जियोरेफेंसिंग में त्रुटि, छूटे हुए खसरों अथवा जियोरेफेंसिड नक्शा उपलब्ध नहीं होने वाले ग्रामों में अनिवार्य रूप से मैनुअल गिरदावरी कराई जाएगी। गिरदावरी कार्य के लिए ग्रामवार एवं ग्राम पंचायतवार कार्यक्रम निर्धारित कर ग्रामीणों को सूचना देने, कोटवार के माध्यम से मुनादी कराने तथा हल्का पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी एवं पंचायत सचिव के संयुक्त दल से मैदानी जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्धारित समय-सारणी के अनुसार गिरदावरी कार्य पूर्ण कर खसरा एवं 'भुईयां' सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि 20 सितंबर 2026 तक, ग्रामवार फ़सल क्षेत्राच्छदन प्रतिवेदन का प्रारंभिक प्रकाशन 25 सितंबर तक तथा दावा-आपत्ति के अनुसार संशोधन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित है।

कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। गिरदावरी कार्य के निरीक्षण के बाद कलेक्टर विश्वदीप ने जागला समिति पहुंचकर एग्रीस्टैक पंजीयन की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से किसानों के पंजीयन एवं एकीकृत किसान आईडी की स्थिति के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल (छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री) पर एकीकृत किसान आईडी के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र किसानों को एग्रीस्टैक पंजीयन की जानकारी देकर उनका पंजीयन समय पर पूर्ण कराया जाए, ताकि किसानों को धान उपार्जन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। निरीक्षण के दौरान प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख बीजापुर मुकेश देवांगन, संबंधित हल्का पटवारी, सर्वेयर एवं अन्य मैदानी अमला उपस्थित रहा।



कोंडागांव। शासकीय गुण्डाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोंडागांव में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने तथा स्वास्थ्य एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने की शपथ दिलाई गई। यह कार्यक्रम महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सरला आत्राम के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (रै) के कार्यक्रम अधिकारी समलेश पोटाई के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों सहित महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागिता के साथ नशा मुक्ति की

शपथ ली। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. सरला आत्राम ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार एवं भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से सदैव दूर रहने तथा अपने साथियों एवं समाज के अन्य लोगों को भी नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में डॉ. किरण नुस्टी, डॉ. पुरोहित कुमार सोरी, शोभा राम यादव सहित महाविद्यालय के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम अनुशासन एवं सक्रिय सहभागिता के साथ सभ्यतापूर्वक संपन्न हुआ।

पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा और कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने हरी झंडी दिखाकर साइबर जागृति रथ को किया रवाना



कोंडागांव। 15 अगस्त से 02 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में जिले के सभी थाना-चौकियों के साथ स्कूल, कॉलेज, हॉट बाजार और कोचिंग सेंटरों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। छात्र, शिक्षक, व्यापारी और आम नागरिक इसमें बड़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोंडागांव जिले में जागरूकता को और तेज करने के लिए पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा और कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने हरी झंडी दिखाकर साइबर जागृति रथ को रवाना किया। साइबर जागृति रथ जिले के गांव, बाजार, स्कूल और कॉलेजों में जाकर

लोगों को साइबर ठगी से बचने के उपाय बताएगा। रथ के माध्यम से फि शिंग, व्च् धोखाधड़ी, फजी लिंक, नकली ऐप और सोशल मीडिया फ्रॉड की जानकारी दी जाएगी। साथ ही लोगों को फ्त कोड स्कैन कर जागरूकता की एक सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आजकल साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए सतर्क रहें। किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, व्च् किसी को न बताएं और ऐप केवल भरोसेमंद जगह से ही डाउनलोड करें। किसी भी सदिग्ध

मामले की सूचना तुरंत 1930 या साइबर सेल को दें। आइए, हम सब मिलकर साइबर क्राइम मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएं और जागरूकता की एक सेल्फी लेकर इस अभियान का हिस्सा बनें। उक्त कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल, उप पुलिस अधीक्षक शिवा सिंह सलामे, टी आई सौरभ उपाध्याय, रक्षित निरीक्षक मनीष सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। साथ ही पीएम आत्मानंद स्कूल एमजी वार्ड कोंडागांव की छात्राएं सम्मिलित हुईं और साइबर जागृति अभियान के बारे में जानकारी ली।

कलेक्टर ने शैक्षणिक संस्थानों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के कि यान्वयन की समीक्षा की



कोंडागांव। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना की अध्यक्षता में मंगलवार को आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के सुचारू अनुपालन एवं क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने, दस्तावेजों का परीक्षण करने तथा पात्र विद्यार्थियों के प्रकरणों को समय-सीमा में स्वीकृत करने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देशित किया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएं, ताकि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ समय

पर मिल सके। उन्होंने छात्रवृत्ति के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित संस्थान प्रमुखों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में स्वीकृत सीटों के विरुद्ध प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या की भी जानकारी ली। उन्होंने शेष रिक्त सीटों पर नियमानुसार प्रवेश की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित प्राचार्यों को दिए। इस अवसर पर आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त कुपेन्द्र तिवारी सहित जिले के सभी महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थानों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य उपस्थित रहे।

कांकेर में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का बड़ा शक्ति प्रदर्शन: 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग, मांगों को लेकर कलेक्टर को साँपा ज्ञापन



कांकेर। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जिला इकाई - उत्तर बस्तर कांकेर के तत्वावधान में जिला मुख्यालय के नरहर देव स्कूल मैदान में एक दिवसीय विशाल जनसभा का आयोजन संपन्न हुआ। इस महारली और जनसभा में कांकेर, कोंडागांव तथा बस्तर संभाग के अन्य जिलों से लगभग 10 हजार की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। संबोधन के पश्चात नरहर देव स्कूल मैदान से समाज के लोगों ने पैदल विशाल रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन साँपा। वक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी न्यायसंगत मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को बस्तर से लेकर रायपुर विधानसभा और दिल्ली लोकसभा तक ले जाया जाएगा। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की तत्काल प्रभाव से 27 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए। जातिगत जनगणना एवं पृथक कॉलेम: आगामी

राष्ट्रीय जनगणना में पिछड़ा वर्ग के लिए एक पृथक कॉलेम शामिल कर संपूर्ण जातिगत जनगणना कराई जाए। संवैधानिक एवं प्रशासनिक संरक्षण: ओबीसी समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा हेतु इसे संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों/संरक्षण में शामिल किया जाए। जनसभा के दौरान मंच से विभिन्न समाज प्रमुखों ने एकजुटता, हक-अधिकार और भविष्य की रूपरेखा पर अपनी बात रखी। कमल किशोर कश्यप: देश की आजादी के 80 वर्ष बीत जाने के बाद भी पिछड़ा वर्ग की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। जब तक समाज अपनी सामूहिक ताकत नहीं दिखाएगा, सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। वर्ष 2013 से हमारा आंदोलन जारी है, लेकिन आज स्थिति यह है कि पंच चुनाव लड़ने के अधिकारों पर भी असर पड़ा है। बस्तर की 11 सीटें राज्य के राजनीतिक समीकरण तय करती हैं, ऐसे में समाज की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, 57 प्रकरणों में 562 लीटर शराब जप्त

भटगांव। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के कड़े निर्देशों और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरेंद्र पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी दीपिका मिज के मार्गदर्शन में भटगांव पुलिस ने अवैध शराब बिक्री करने वाले कोचियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रखी है। जहां थाना प्रभारी उपनिरीक्षक शिवकुमार धारी के कुशल नेतृत्व में बीते 2 दिनों में क्षेत्र में 2 बड़ी छापामार कार्रवाइयां की गईं। पुलिस ने ग्राम सलोनीकला के सबरिया डेरा और ग्राम चुरेला में दबिश देकर 2 शराब कोचियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से कुल 45 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक भटगांव थाना क्षेत्र में आबकारी एक्ट के 57 प्रकरणों में कुल 562 लीटर अवैध शराब जप्त की जा चुकी है। वहीं मुखबि की सूचना पर ग्राम सलोनीकला क्षेत्र के सबरिया डेरा और चुरेला गांव में कुछ लोग अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बनाकर बिक्री कर रहे थे सूचना की सत्यता की जांच के बाद थाना प्रभारी शिवकुमार धारी ने एक विशेष टीम गठित कर तत्काल दबिश दिए। पहली कार्रवाई - ग्राम सलोनीकला, सांवरिया डेरा 18



अगस्त की शाम टीम ने सबरिया डेरा में दबिश दी। यहां पुलिस ने आरोपी लच्छी गोंड पिता शंकर गोंड, उम्र 23 वर्ष, निवासी सबरिया डेरा, सलोनीकला, थाना भटगांव, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को 30 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ रो हाथों पकड़ा। जप्त शराब की अनुमानित कीमत 6,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं दूसरी कार्रवाई ग्राम चुरेला में 19 अगस्त की सुबह चुरेला गांव में कार्रवाई कर आरोपी दीपक मनहर पिता कुपाराम मनहर, उम्र 25 वर्ष, निवासी चुरेला, थाना भटगांव, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 15 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब बरामद हुई।

पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने बेदरे थाना का औचक निरीक्षण किया गया



बीजापुर। पुलिस अधीक्षक बीजापुर उमेश प्रसाद गुप्ता द्वारा थाना बेदरे का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, अभिलेखों एवं विभिन्न रजिस्ट्रों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी, विवेचकों एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारियों से थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ेबेंदरी का राष्ट्रीय स्तर इंस्पायर अवार्ड मानक हेतु चयन

कोंडागांव। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ेबेंदरी ने एक बार फिर विज्ञान के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। विद्यालय के प्राचार्य संजय ठाकुर के संरक्षण एवं व्याख्याता अंकित गुप्ता एवं दिलीप कश्यप के मार्गदर्शन में विद्यालय की छात्रा मिथिला कोराम ने इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता के राज्य स्तरीय चरण में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर हेतु चयनित होकर विद्यालय, क्षेत्र एवं जिले का गौरव बढ़ाया है। मिथिला कोराम ने अपने अभिनव वैज्ञानिक विचार एवं मॉडल के माध्यम से राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस सफलता में मार्गदर्शक शिक्षक अंकित गुप्ता एवं दिलीप कश्यप का विशेष योगदान रहा। दोनों शिक्षकों ने छात्रा को वैज्ञानिक सोच विकसित करने, मॉडल को बेहतर स्वरूप देने तथा प्रतियोगिता की तैयारी में निरंतर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन दिया। उनके समर्पण और सकारात्मक मार्गदर्शन ने मिथिला के आत्मविश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



विद्यालय के प्राचार्य संजय ठाकुर ने मिथिला कोराम एवं उनके मार्गदर्शक शिक्षकों को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि मिथिला राष्ट्रीय कर्यप का विशेष योगदान रहा। दोनों शिक्षकों ने छात्रा को वैज्ञानिक सोच विकसित करने, मॉडल को बेहतर स्वरूप देने तथा प्रतियोगिता की तैयारी में निरंतर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन दिया। उनके समर्पण और सकारात्मक मार्गदर्शन ने मिथिला के आत्मविश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विद्यालय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मक सोच एवं प्रयोगात्मक शिक्षा की निरंतर बढ़ावा दिया जाता है। शिक्षकों के समर्पित प्रयासों और विद्यार्थियों की प्रतिभा के परिणामस्वरूप विद्यालय प्रत्येक वर्ष विज्ञान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान एवं नए बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। मिथिला कोराम का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन विद्यालय की इसी गौरवशाली यात्रा की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है। विद्यालय परिवार ने मिथिला एवं उनके मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सफ लता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

डीईओ जे. आर. डहरिया का आज विकासखण्ड बिलाईगढ़ के विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण

शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश

भटगांव। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी जे.आर.डहरिया ने बुधवार को विकास खण्ड बिलाईगढ़ के शासकीय प्राथमिक शाला भारतपुर, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भारतपुर, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मलदी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरागांव के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का गहन जायजा लेते हुए शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पठन-पाठन और विद्यालयी व्यवस्थाओं की ली जानकारी निरीक्षण के दौरान



डीईओ ने छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, शिक्षकों की नियमितता, पठन-पाठन की गुणवत्ता, मध्याह्न भोजन, पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय तथा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई का निरीक्षण किया।

उन्होंने उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया। बच्चों से पूछे सवाल, नियमित पढ़ाई के लिए प्रेरित-डीईओ ने विभिन्न कक्षाओं में पहुंचकर और छात्र-छात्राओं से बातचीत कर विभिन्न

विषयों से जुड़े प्रश्न पूछे। उन्होंने बच्चों की सीखने की क्षमता का आकलन करते हुए नियमित रूप से विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक उनके प्रश्नों का

उत्तर दिया। शिक्षकों को समयबद्धता और गुणवत्ता पर दिया जोर- निरीक्षण के क्रम में डीईओ ने शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुंचने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति

सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है और इसमें शिक्षकों की सक्रिय भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। लापरवाही पर होगी

कार्रवाई, जारी रहेगा निरीक्षण- डीईओ ने विद्यालय के अभिलेखों की भी जांच की और आवश्यक सुधार के लिए संबंधित शिक्षकों को निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शैक्षणिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के अंत में उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।

संपादकीय

रेलवे स्टेशनों से लेकर ट्रेन में सफर के दौरान परोसे या बेचे जाने वाले खानपान की घटिया गुणवत्ता के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। मगर कैग की रिपोर्ट में पीने के पानी में भी जिस तरह की गड़बड़ी बताई गई है, उससे व्यापक लापरवाही का ही पता चलता है।गौरतलब है कि हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की

एक रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए कि देश के कई रेलवे स्टेशनों के पानी में ई-कोलाई और कोलीफार्म जैसे जीवाणु पाए गए हैं। इस दौरान पांच सौ बारह स्टेशनों की जांच में चार सौ अड्डवन पर जरूरी यात्री सुविधाओं की कमी मिली।रेल महकमा समय-समय पर किराया बढ़ाने को लेकर तो जरूरत से ज्यादा सजग दिखता है, लेकिन स्वच्छ

पेयजल जैसी सबसे जरूरी चीज की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने की उसे शायद कोई फिक्र नहीं है। लोगों को या तो स्टेशन पर लगे नल से असुरक्षित पानी पीना पड़ता है या फिर बोतलबंद पानी खरीदना पड़ता है।अब भले रेलवे ने पेयजल की गुणवत्ता सुधारने की बात कही है, लेकिन यह कब संभव होगा, यह देखने की बात होगी। यह जगजाहिर

तथ्य है कि ट्रेन से अपने गंतव्य के लिए निकले लोग कई बार एक या दो दिन की लंबी यात्रा भी करते हैं। इस दौरान पानी न मिलने या फिर दूषित पेयजल की वजह से लोगों की सेहत बिगड़ने के मामले जब-तब सामने आते रहते हैं।सवाल है कि अगर टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को स्वच्छ पेयजल जैसी सबसे बुनियादी चीज भी

मुश्किल से मिल पाती है, तो सरकार किस भरोसे भारतीय रेल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के दावे करती रहती है! कुछ महंगी और अति-महत्त्वपूर्ण मानी जाने वाली ट्रेनों को छोड़ दें, तो क्या साधारण लोगों के लिए भी रेल यात्रा उतनी ही सहज या सुकूनदेह रह गई है?ट्रेन में सीट पर आराम से बैठ कर यात्रा कर पाना जहां

चुनौती बन चुकी है, वहीं सफर के दौरान खाने-पीने का सामान कैसा मिलता है, यह अब कोई छिपी हकीकत नहीं रह गई है। मगर सबसे बुनियादी चीज- पीने के पानी तक की हालत अगर ऐसी है कि ज्यादातर स्टेशनों पर लगे नले से दूषित पेयजल मिलता है, तो इससे उपजे जोखिम के लिए कौन जिम्मेदार है?

पीएम मोदी का लालकिले से विकसित भारत का संकल्प

(अशोक भाटिया)
इस व्यापक संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए देश के चार प्रमुख वर्गों को विकास का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिन्हें युवा, महिला, किसान और गरीब के रूप में रेखांकित किया गया है। इन चारों स्तंभों के समग्र सशक्तिकरण के बिना किसी भी विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।

ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर केवल पथरों की एक संरचना नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के उदार-चक्रवर्त, उसकी आकांक्षओं, उसकी नियति और उसके सामूहिक संकल्पों की मुक्त गवाह रही है। हर वर्ष 15 अगस्त को इस प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो वह केवल एक औपचारिक भाषण नहीं होता, बल्कि वह आने वाले समय के लिए देश का नीतिगत और वैचारिक रोडमैप होता है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी ऐतिहासिक प्राचीर से वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो अटूट संकल्प दोहराया है, वह देश की समकालीन राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक युगांतकारी मोड़ है। विकसित भारत का यह विजन महज एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक चेतना को जगाने और उन्हें राष्ट्र निर्माण के एक महायज्ञ में आहुति देने के लिए प्रेरित करने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय दर्शन है। जब हम इस विराट संकल्प की बात करते हैं, तो हमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ और प्रार्संगिकता को गहराई से समझना होगा। भारत ने लगभग दो सदियों तक औपनिवेशिक दासता और आर्थिक शोषण का दंश झेला है। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तब हमारी अर्थव्यवस्था जर्जर थी, साक्षरता दर दयनीय थी और अकाल तथा गरीबी जैसी बुनियादी चुनौतियां हमारे सामने थीं। शुरुआती दशकों में भारत का मुख्य ध्यान आत्मनिर्भरता और बुनियादी अस्तित्व की रक्षा पर था। हमने खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति की, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य तंत्र को मजबूत किया और धीरे-धीरे एक ठोस औद्योगिक आधार तैयार किया। आज, स्वतंत्रता के इस दौर में, भारत उस स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है और अब हम केवल एक अस्तित्व बनाए रखने वाले देश नहीं हैं, बल्कि हम वैश्विक पटल पर एक नई दिशा तय करने वाले राष्ट्र बन चुके हैं। यह संकल्प इस बात का प्रतीक है कि अब भारत अपनी विकासशील छवि के खोल को तोड़कर वैश्विक शक्तियों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2047 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष होगा, और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर दुनिया के सामने अपनी सफलता का क्या प्रमाण प्रस्तुत करता है, यही उसका वास्तविक ऐतिहासिक मूल्यांकन होता है।

इस व्यापक संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए देश के चार प्रमुख वर्गों को विकास का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिन्हें युवा, महिला, किसान और गरीब के रूप में

रेखांकित किया गया है। इन चारों स्तंभों के समग्र सशक्तिकरण के बिना किसी भी विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है और हमारी जनसांख्यिकीय लाभांश हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विकसित भारत का सपना तभी सच हो सकता है जब इस युवा ऊर्जा को सही दिशा, उत्कृष्ट शिक्षा और वैश्विक स्तर का कौशल मिले। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को रोजगारीन्मुख बनाना इसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। इसके साथ ही, विकसित भारत का दूसरा अनिवार्य पहलू महिलाओं का सशक्तिकरण और उनके नेतृत्व में होने वाला विकास है। जब तक देश की आधी आबादी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से



पूरी तरह सक्रिय नहीं होगी, तब तक विकास की रफ्तार अधूरी रहेगी। सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती महिलाओं की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि वे अब नीति निर्धारण के केंद्र में आ रही हैं। इसी तरह, भारत की आत्मा आज भी गांवों में बसती है और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार, आधुनिक खेती को बढ़ावा और वैश्विक कृषि आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना आवश्यक है। किसान जब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक कृषि-उद्यमी बनेगा, तभी ग्रामीण भारत समृद्ध होगा। अंत में, अंत्योदय की भावना के अनुरूप समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को तब तक विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक कि बहुआयामी गरीबी का पूरी तरह उन्मूलन न हो जाए और हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन स्तर न मिल जाए।

आर्थिक मोर्चे पर, भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और शीर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की ओर अग्रसर है। लेकिन विकसित देश बनने के लिए हमें केवल सकल घरेलू उत्पाद के आकार को ही नहीं बढ़ाना है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय और नागरिकों के जीवन की

गुणवत्ता में भी गुणात्मक सुधार करना होगा। इसके लिए विनिर्माण और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल देना आवश्यक है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। रक्षा क्षेत्र में, जहां कभी हम पूरी तरह आयातों पर निर्भर थे, आज हम स्वदेशी अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं और उनका निर्यात भी बढ़ा रहे हैं। भारतीय कॉर्पोरेट जगत को अब वैश्विक कंपनियों की तर्ज पर अपनी क्षमता का विस्तार करना होगा ताकि भारतीय ब्रांड दुनिया भर के बाजारों में अग्रणी भूमिका निभा सकें। इसके साथ ही, देश के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प किया जा रहा है। आधुनिक रेलवे, एक्सप्रेसवे का विस्तृत नेटवर्क, जलमार्गों का विकास



और हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक मजबूत और आधुनिक बुनियादी ढांचा ही विकसित भारत की ठोस नींव बनेगा, जो देश के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगा।

तकनीक और नवाचार के इस युग में जो देश अग्रणी रहेगा, वही दुनिया के भविष्य को दिशा देगा। भारत ने डिजिटल क्षेत्र में जो क्रांति की है, उसने दुनिया के विकसित देशों को भी अचंभित किया है। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था आज वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बन चुकी है। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं है, बल्कि वह विश्व को सस्ती, सुरक्षित और समावेशी तकनीक देने वाला प्रदाता भी है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में बढ़ता निवेश इस विजन को और स्पष्ट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रांतिम कंयूटिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत का बढ़ता कदम यह दर्शाता है कि हम भविष्य की तकनीकों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और संप्रभु होना विकसित भारत की एक अनिवार्य शर्त है, जो हमें वैश्विक मंच पर एक अद्वितीय पहचान

दिलाएगी।

संकल्प जितना विराट होता है, उसकी राह की चुनौतियां भी उतनी ही कठिन होती हैं। विकसित भारत के मार्ग में कई आंतरिक और बाह्य चुनौतियां हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश की आर्थिक प्रगति के साथ-साथ क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता को पाटना एक बड़ी चुनौती है। विकास का लाभ समाज के हर वर्ग और देश के हर कोने तक समान रूप से पहुंचना चाहिए। इसके अलावा, भारत को पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच एक कुशल संतुलन बनाना होगा। जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना युद्धस्तर पर आवश्यक है। प्रशासनिक स्तर पर, हमारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-अनुकूल बनना होगा, क्योंकि लालफीताशाही और भ्रष्टाचार विकास की गति को धीमा करते हैं। वैश्विक मोर्चे पर, वर्तमान समय की भू-राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक व्यवधान भी हमारे सामने चुनौतियां खड़ी करते हैं, जिनसे निपटने के लिए भारत को अपनी कूटनीतिक कुशलता और आंतरिक आर्थिक सुदृढ़ता को निरंतर मजबूत बनाए रखना होगा।

इस पूरे महायज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश के नागरिकों की है। कोई भी देश

केवल सरकार की नीतियों, बजट या घोषणाओं से विकसित नहीं बनता। सरकार माफ़ प्रशस्त कर सकती है, बुनियादी ढांचा दे सकती है, लेकिन उस पर चलकर देश को आगे ले जाने का काम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से ही संभव होता है। विकसित भारत का संकल्प तब तक अधूरा है जब तक देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सजग नहीं होता। चाहे वह करोों का ईमानदारी से भुगतान करना हो, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हो, पर्यावरण को बचाना हो, या फिर अपने-अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ योगदान देना हो-ये सभी नागरिक प्रयास मिलकर एक विशाल राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करते हैं। जब देश के नागरिक राष्ट्र प्रथम की भावना को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेंगे, तो भारत की प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा। निष्कर्षतः विकसित भारत का संकल्प केवल आर्थिक आंकड़ों या ऊंची इमारतों तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, तकनीकी रूप से अग्रणी हो, सामाजिक रूप से समरस और न्यायपूर्ण हो, और सांस्कृतिक रूप से अपनी समृद्ध जड़ों से जुड़ा हुआ हो। यह एक ऐसे भारत का सपना है जहां हर नागरिक को समान अवसर, उत्कृष्ट शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा मिले।

विभाजन विभीषिका- हिन्दू नरसंहार की मर्मांतक दास्तां

(कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल)

हमें ये जानना जरूरी है कि उस समय भारत विभाजन के लिए किस प्रकार से अंग्रेज अपनी चाल चल रहे थे? मुस्लिम लीग किस प्रकार से दंगों के आतंकी वक्रर चेहरे के रूप में उभर रही थी? कैसे पंडित नेहरू मुस्लिम लीग की ज़िद के आगे घुटने टेक रहे थे? दरअसल, भारत विभाजन को लेकर



जब अंग्रेजों ने पटकथा रची तो वो हर वो दांव-पेंच आजमा रहे थे।

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन हुआ लेकिन स्वाधीनता के साथ विभाजन की वीभत्स त्रासदी ने राष्ट्र को कभी न भर पाने वाले असह्य घाव दिए। उस समय हुए हिन्दुओं के नरसंहार और उसकी पीड़ा से पूरा देश कांप गया। जिसकी मर्मांतक चीखें अब भी सुनाई देती हैं।अतीत को जानना आवश्यक हो जाता है।आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि उस समय भारत विभाजन के लिए किस प्रकार से अंग्रेज अपनी चाल चल रहे थे? मुस्लिम लीग किस प्रकार से दंगों के आतंकी वक्रर चेहरे के रूप में उभर रही थी? कैसे पंडित नेहरू मुस्लिम लीग की ज़िद के आगे घुटने टेक रहे थे? दरअसल, भारत विभाजन को लेकर जब अंग्रेजों ने पटकथा रची तो वो हर वो दांव-पेंच आजमा रहे थे। जो कि उनके मंसूबों को पूरा कर सके। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत विभाजन के लिए आए माउंटबेटन और उसकी पत्नी एडविना के साथ 10 मई 1947 से कई दिनों तक शिमला में पार्टियां कर रहे थे। इतना ही नहीं माउंटबेटन ने एल्लिजबेथ द्वारा दी गई महंगी कार रोल्स रॉयस पंडित नेहरू को दी थी। नेहरू इसी में यात्राएं करते थे। फिर शिमला में

के लिए मुस्लिम लीग और जिन्ना तो उतावले थे ही साथ ही पंडित नेहरू की भी भूमिका सदिश्य और विभाजन के पक्ष में ही स्पष्ट प्रतीत होती है।

उस समय काँग्रेस कार्यसमिति द्वारा भारत विभाजन की माउंटबैटन योजना को स्वीकार करने की तैयारियों का महात्मा गांधी ने भी विरोध किया था। लेकिन उनकी आगे नहीं चली और 3 जून 1947 को पंडित नेहरू की अगुवाई में काँग्रेस ने अंग्रेजों के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस सन्दर्भ में मनु गांधी से 1 जून 1947 को चर्चा की थी। मनु को अपने दिल की बात कहते हुए महात्मा गांधी ने बताया— आज मैं अपने को अकेला पाता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वह एक भूल है। भले ही मैं काँग्रेस का चवन्नी का सदस्य नहीं हूँ लेकिन वे सब लोग मुझे पछ्ते है, मेरी सलाह लेते है। आजादी के कदम उलटे पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आज इसके परिणाम तत्काल दिखाई न दें, लेकिन हिन्दुस्तान का भविष्य मुझे अच्छ नहीं दिखाई देता। हिन्दुस्तान की भावी पीढ़ी की आह मुझे न लगे कि हिंदुस्तान के विभाजन में गांधी ने भी साथ दिया था। (गांधी सम्पूर्ण वॉमपय, खंड 88, पृष्ठ 43-44)।

अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026- 79 प्रतिशत योगदान, फिर भी जमीन के हक से दूर महिला किसान

(मनीष अग्रहारि)

अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026- देश में 75 प्रतिशत कृषि कार्य महिलाओं द्वारा किए जाने के बावजूद मात्र 14 प्रतिशत भूमि पर उनका मालिकाना हक है। इस लैंगिक असमानता को दूर कर महिला किसानों को पहचान, भूमि अधिकार, वित्तीय लाभ व उचित सम्मान देना अनिवार्य है।

संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के कृषि एवं बागवानी के कार्यों में महत्त्व को मान्यता देने और लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में महिलाओं की आबादी 48.4 फीसद है, इसके बावजूद खेती और बागवानी में उनकी आधे से भी अधिक की भागीदारी है।

ग्रामीण महिलाएं दैनिक श्रमसाध्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ-साथ बागवानी से जुड़े कार्यों में 79 फीसद तथा खेती में लगभग 75 फीसद सक्रिय हिस्सेदारी करती हैं, फिर भी यह कटु सत्य है कि किसान तो पुरुष ही कहलाता है। जब भी किसान की बात आती है, तो हम सबके मन-मस्तिष्क में प्रायः पुरुष किसान ही उभरता है।

ऐसे विरोधाभास में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर सरकार और समाज को देश की महिला किसानों के उत्थान के लिए संजीदगी से विचार करना होगा, क्योंकि आज भी वास्तविकता से हटकर पूरी दुनिया में महिला किसानों के महत्त्वपूर्ण योगदान के बावजूद उनके कार्यों को हाशिये पर रखा जाता है।

देश में उदारीकरण, निजीकरण और औद्योगीकरण के बाद पुरुषों का गांवों से पलायन बढ़ा है। ऐसे में महिलाओं ने रोजमर्रा के घरेलू कार्यों के साथ-साथ कृषि एवं संबद्ध कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभानी शुरू की है। आज यंत्रीकरण के बावजूद भाग की रोपाई करते हुए आमतौर पर महिलाएं ही देखी जाती हैं। इसके अलावा

संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के कृषि एवं बागवानी के कार्यों में महत्त्व को मान्यता देने और लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में महिलाओं की आबादी 48.4

फीसद है, इसके बावजूद खेती और बागवानी में उनकी आधे से भी अधिक की भागीदारी है। ग्रामीण महिलाएं दैनिक श्रमसाध्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ-साथ बागवानी से जुड़े कार्यों में 79 फीसद तथा खेती में लगभग 75 फीसद सक्रिय हिस्सेदारी करती हैं, फिर भी यह कटु सत्य है कि किसान तो पुरुष ही कहलाता है। जब भी किसान की बात आती है, तो हम सबके मन-मस्तिष्क में प्रायः पुरुष किसान ही उभरता है।

वे सारे कार्य जो खेती में श्रम प्रधान हैं, जैसे- बुआई, गुड़ाई, कटाई, ओसाई, भंडारण, प्रसंस्करण तथा चारा उत्पादन, ये सभी सर्वाधिक महिलाओं के खाते में ही दर्ज होते हैं।

मत्स्य पालन, पशुपालन और बागवानी में भी कमोबेश यही स्थिति है। इसके बावजूद राजस्व अभिलेखों में इनका अदृश्य होना अनेक सवाल खड़ा करता है। वर्ष 2023-24 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, देश में प्रत्येक तीन में से दो ग्रामीण महिलाएं कृषि समुदाय का हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अस्सी फीसद महिलाएं कृषि में संलग्न हैं।

इसी तरह लोकसभा में दी गई सूचना के अनुसार, महिला कृषि श्रमिकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी तरफ पुरुष कृषि श्रमिकों में गिरावट देखने को मिल रही है। जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार, देश में 3.6 करोड़ महिला किसान तथा 6.15 करोड़ महिला कृषि श्रमिक हैं। इस तरह, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी होने के बावजूद उन्हें पूरे हक-हक्क नहीं मिल पा रहे हैं।

यही कारण है कि महिला किसानों और श्रमिकों की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद तकरीबन चौदह फीसद महिला किसानों का नाम ही कृषि योग्य भूमि एवं राजस्व अभिलेख में अंकित है। इसी तरह महिला कृषि

श्रमिकों के नाम महज दो फीसद ही हैं। वर्ष 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार, पंजाब जैसे समृद्ध राज्य में महिलाओं के नाम अभी भी कृषि योग्य भूमि पर मात्र एक फीसद ही दर्ज हैं।

ऐसा नहीं है कि खेती में महिलाओं की हकदारी में असमानता सिर्फ भारत में ही है, बल्कि पूरी दुनिया में उनके नाम खेत का स्वामित्व न होना एक बड़ा विषेद खड़ा करता है। एक अनुमान के मुताबिक, विकासशील देशों में आधी से अधिक आबादी खेती में संलग्न है, मगर भूमि का स्वामित्व सिर्फ पंद्रह फीसद महिलाओं के पास ही है। इस तरह कृषि के क्षेत्र में पूरी दुनिया में लैंगिक असमानता कायम है। देश में महिला किसानों की तरकी में सबसे बड़ा रोड़ा अभिलेखजनित असमानता ही है, क्योंकि खेती योग्य भूमि का स्वामित्व (खसरा, खतौनी में नाम) न होने के कारण अनेक प्रकार की सरकारी योजनाओं और औपचारिक वित्तीय लाभ खासतौर से किसान क्रेडिट कार्ड एवं सरकारी अनुदान से महिलाएं कोसों दूर हो जाती हैं। लागत को घटाने के लिए इस समय कृषि यंत्रों पर जोर है, मगर महिलाओं के अनुकूल कृषि यंत्र बहुत कम उपलब्ध हैं। सरकार को इस मसले पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। महिलाएं देश, समाज और परिवार के लिए कितना योगदान दे रही हैं, उसे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के

आंकड़ों से समझा जा सकता है। इसके अनुसार, महिलाएं चूल्हा-चौका, बच्चों के पालन-पोषण समेत अन्य घरेलू कार्यों के दबाव के चलते तकरीबन ढाई गुना से अधिक समय अवैतनिक कार्यों में गुजार देती हैं। इससे उनका बाजार उन्मुखीकरण और उच्च मूल्य वाले कार्यों में भागीदारी मूल्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होने की संभावना सर्वाधिक न्यून हो जाती है।

संविधान का अनुच्छेद-14 सभी को समानता का अधिकार देता है, इससे महिलाओं को सामान कार्य का सामान मेहनताना मिलना चाहिए। मगर संवैधानिक व्यवस्था से इतर महिलाओं को व्यावहारिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा कृषि कार्यों का मेहनताना कम दिया जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद- 21 गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देता है, मगर कृषि क्षेत्र के असंगठित होने के कारण कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध अधिनियम, 2013 भी लागू नहीं हो पाता है। केवल संगठित और बड़े कार्यस्थलों में ही यह मुर्त रूप ले पाता है। इससे खेती आधारित गतिविधियों में कई बार महिलाएं यौन उत्पीड़न और हिंसा की शिकार हो जाती हैं और न्याय के लिए उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है। ऐसे में संविधान प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन और समानता की बात कल्पना से परे है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली कृषि अनुसंधान एवं प्रसार की

सर्वोच्च संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महिला किसानों के उत्थान के लिए वर्ष 1996 में भुवनेश्वर में केंद्रीय महिला कृषि संस्थान की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य कृषि में महिलाओं के अनुरूप तकनीक और आजीविका पर केंद्रित अनुसंधान करना है। इसी प्रकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ा है, नमो ड्रोन दीदी योजना से हुनरमंद महिलाएं तरकी की नई इबारत लिख रही हैं, लवंपति दीदी योजना से भी लाभ हो रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के संयुक्त सहयोग से एग्री क्लीनिक और एग्री बिजनेस सेंटर योजना के माध्यम से महिला कृषि उद्यमी तैयार हो रही हैं। इसी तरह कृषि संवर्धनका कोष समेत अनेक योजनाएं आज संचालित हो रही हैं। फिर भी वास्तविक किसान के रूप में जमीन का मालिकाना हक न मिल पाने के कारण दिन-रात खेत में कार्य करने वाली महिला किसानों को नवाचारों में निरर्थक लेने की शक्ति, कृषि उत्पादों में सौदेबाजी, संस्थागत कर्ज लेने और सब्सिडी की सुविधा नहीं मिल पाती है। अब यह समय की मांग है कि सरकार, निजी संस्थाएं और समाज तीनों मिलकर महिला किसानों को खेती जैसे महत्त्वपूर्ण संसाधन के हक-हक्क दिलाने के लिए नीतिगत निर्णय के साथ उन्हें समान अधिकार और सम्मान दिलाएं।



वाणिज्य विभाग की स्पेशल टीम ने बिलासपुर स्टेशन पर बिछड़े दृष्टिबाधित यात्री को सुरक्षित परिजनों से मिलाया



बिलासपुर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर वाणिज्य विभाग की 'स्पेशल सेल' ने तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए परिवार से बिछड़े एक दृष्टिबाधित (नेत्र दिव्यांग) यात्री को सुरक्षित खोजकर उनके परिजनों से मिलाया। जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर एक परिवार बिलासपुर से नागपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा था। स्टेशन परिसर में यात्रियों की आवाजाही के दौरान परिवार का एक दृष्टिबाधित सदस्य अचानक अपने परिजनों से अलग हो गया। यात्री के लापता होने से चिंतित परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना ऑन-ड्यूटी 'स्पेशल सेल' को दी। सूचना मिलते ही स्पेशल सेल की टीम ने बिना समय गंवाए स्टेशन परिसर में खोजबीन शुरू की। टीम ने स्टेशन के विभिन्न हिस्सों में सघन तलाश करते हुए कुछ ही समय में यात्री को सुरक्षित खोज निकाला और उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द किया। अपने परिजन को सकुशल पाकर परिवार ने राहत की सांस ली। परिजनों ने स्पेशल सेल की त्वरित कार्रवाई, संवेदनशीलता और सहयोग के लिए रेलवे प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात पूरा परिवार सुरक्षित रूप से नागपुर के लिए रवाना हुआ। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह ने बताया वाणिज्य विभाग की स्पेशल सेल द्वारा की गई यह त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई, यात्रियों, विशेषकर दिव्यांग एवं जरूरतमंद यात्रियों की सहायता के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध बिलासपुर स्टेशन में चला नाका टिकट चेकिंग अभियान

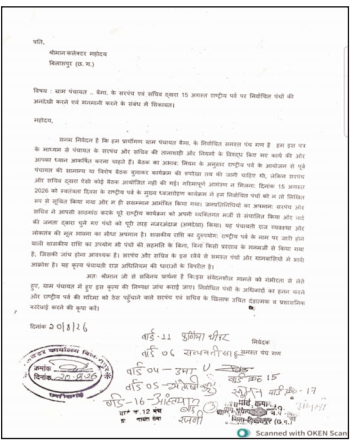


बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल द्वारा टिकटधारी यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने, यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से निरंतर टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 20 अगस्त 2026 को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में मंडल के बिलासपुर स्टेशन एवं चांपा-बिलासपुर-भाटापारा सेक्शन में सघन नाका टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें वाणिज्य निरीक्षक, मुख्य टिकट निरीक्षक एवं टीटीई स्टाफशामिल थे। इस अभियान के दौरान बिलासपुर स्टेशन एवं यहाँ से गुजरने वाली 26 ट्रेनों की सघन जांच कर कुल 385 मामलों से कुल 3,17,410 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जिसमें बिना टिकट यात्रा के 285 मामलों से 02 लाख 59 हजार 800 रुपये, अनियमित टिकट के 77 मामलों से 55 हजार 105 रुपये तथा बिना बुक किए गए टोकेज के 23 मामलों से 02 हजार 505 रुपये का जुर्माना शामिल है रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व उचित यात्रा टिकट अवश्य लें तथा स्टेशन परिसर में प्रवेश हेतु प्लेटफॉर्म टिकट खरीदें। साथ ही रेलगाड़ी एवं रेलवे परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें तथा गंदगी फैलाने एवं धूम्रपान जैसी गतिविधियों से बचें। रेलवे राष्ट्र की महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति है, इसकी सुरक्षा एवं स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

15 अगस्त आयोजन में पंचों की अनदेखी का आरोप,ग्राम पंचायत बैमा में विवाद...

बिलासपुर। ग्राम पंचायत बैमा में 15 अगस्त 2026 के राष्ट्रीय पर्व के आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पंचायत के निर्वाचित पंचों ने सरपंच और सचिव पर नियमों की अनदेखी,मनमानी तथा पंचों को विश्वास में लिए बिना पंचायत का कामकाज संचालित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पंचों ने मामले को शिकायत कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल से करते हुए निष्पक्ष जांच तथा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पंचों का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के आयोजन को लेकर पंचायत की सामान्य सभा अथवा आवश्यक बैठक नहीं बुलाई गई। 15 अगस्त को आयोजित मुख्य ध्वजारोहण कार्यक्रम में निर्वाचित पंचों को न तो विधिवत सूचना दी गई और न ही सम्मानपूर्वक

आमंत्रित किया गया। पंचों का कहना है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की इस तरह अनदेखी पंचायत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के सम्मान पर गंभीर उपयोग पर भी उठे सवाल- शिकायत में राष्ट्रीय पर्व के आयोजन में पंचायत की राशि के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। पंचों ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम पर सरकारी राशि खर्च करने से पहले आवश्यक प्रक्रिया, प्रस्ताव और पंचायत स्तर पर विचार-विमर्श किया गया या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने आयोजन से संबंधित स्वीकृति, प्रस्ताव, बिल-वाउचर और भुगतान सहित सभी अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही पंचों ने पंचायत के पूर्व कामकाज और बैठकों के रिकॉर्ड की भी जांच की मांग की है। उनका



कहना है कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पंचायत में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैठकें आयोजित की गई या नहीं तथा निर्णय प्रक्रिया में निर्वाचित पंचों को उचित भूमिका दी गई

या नहीं। कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग- पंचों ने जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल को शिकायत सौंपकर पंचायत के कामकाज, स्वतंत्रता दिवस आयोजन और सरकारी राशि के उपयोग से जुड़े आरोपों की जांच की मांग की है। वहीं कलेक्टर संजय अग्रवाल को भी शिकायत देकर प्रशासनिक स्तर पर हस्तक्षेप करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने कहा 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व में लापरवाही निंदनीय- इस मामले पर अंकित गौरहा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक उदासीनता के कारण यदि 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व के आयोजन में भी कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को

सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करना भी आवश्यक नहीं समझा जा रहा है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की एकता,लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा अवसर है। ऐसे कार्यक्रमों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान और उनकी गरिमापूर्ण सहभागिता सुनिश्चित कराना प्रशासन और पंचायत की जिम्मेदारी है। अंकित गौरहा ने कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों अथवा पंचायत पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ ठोस और नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो।

सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करना भी आवश्यक नहीं समझा जा रहा है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की एकता,लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा अवसर है। ऐसे कार्यक्रमों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान और उनकी गरिमापूर्ण सहभागिता सुनिश्चित कराना प्रशासन और पंचायत की जिम्मेदारी है। अंकित गौरहा ने कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों अथवा पंचायत पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ ठोस और नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो।

सुनिश्चित रखने कहा गया। पुलिस विभाग को पर्व के दौरान शहर के समस्त चौक-चौराहों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को पर्व के दौरान निरंतर विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए। इसी प्रकार अन्य विभागों को जिम्मेदारी सौंपते हुए सजग रहने कहा गया। समिति के सदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने का भरोसा दिलाया। बैठक में एडीएम शिवकुमार बनर्जी, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम खंजाची कुमार, एसडीएम मनीष साहू, संयुक्त कलेक्टर रजनी भगत, सीएसपी सिविल लाईन परमेश्वर तिलकवार, शांति समिति के सदस्य हबीब मेमन, चंचल सलूजा, मनजीत सिंह अरोरा, विकास शर्मा, प्रवीण झा, चक्रांत केशरवानी, राजेश मिश्रा, प्रबीर सेन गुप्ता, प्रदीप कुमार शर्मा, सुधीर खण्डेलवाल, इरशाद अली, अनिल कुमार गौरहा अन्य सदस्य एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

ईद-ए-मिलाद एवं गणेश चतुर्थी पर्व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का लिया गया निर्णय

कलेक्टर-एसएसपी की अध्यक्षता में शान्ति समिति की बैठक संपन्न



न हो। इसकी निगरानी रखी जाए। विद्युत तारों से किसी प्रकार की दुर्घटना न हो इसका विशेष ध्यान रखने कहा गया। पंडाल में पर्याप्त स्वयंसेवकों की व्यवस्था हो, इसके निर्देश दिए गए। सभी समितियों, कमिटियों को पर्व के दौरान समितियों द्वारा पुलिस को स्वयंसेवकों की सहायता उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही ईद-ए-मिलाद पर्व के दौरान भी सड़क पर पंडाल लगाकर यातायात बाधित

दिए गए। समितियों को विसर्जन स्थल एवं रूट की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देने के निर्देश दिए गए। सभी पूजा पंडाल एवं आसपास सीसीटीवी कैमरा पंक्ताल एवं आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाया अनिवार्य होगा। पूजा पंडालों में मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग को मंदिरों, मस्जिदों, गणेश पंडालों, संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तथा विसर्जन स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने कहा

गया। सभी पूजा पंडालों एवं आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाना तथा मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करना अनिवार्य किया गया। पर्व के दौरान भंडारा एवं लंगर में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने, दोना-पतल एवं डस्टबिन की व्यवस्था रखने तथा सड़क पर वाहन रुकवाकर प्रसाद वितरण नहीं किया जाए। जिला अस्पताल को भी पर्व के दौरान आवश्यक आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था

महतारी वंदन योजना की किश्त से सोनम साहू के चेहरे पर आई खुशी

राखी का बंधन, खुशियों का संसार, महतारी वंदन से बहनों को संबल अपार

रक्षाबंधन से पहले विष्णु भैया से मिला उपहार



किया जा रहा है। अपनी खुशियां बयां करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से पहले विष्णु भैया से बहनों को संबल मिला है। सोनम साहू ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत प्राप्त राशि का उपयोग वह अपने भाई के लिए रक्षासूत्र (राखी) खरीदने और रक्षाबंधन की अन्य तैयारियों में करेंगी। उन्होंने कहा कि त्योहार के अवसर पर मिलने वाली यह आर्थिक सहायता उनके लिए बेहद उपयोगी है। इससे वे अपनी जरूरतों और

पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह और विश्वास का पर्व है। ऐसे समय में महतारी वंदन योजना की किश्त मिलना उनके लिए खुशी को दोगुना करने वाला है। उन्होंने योजना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिलने से वे अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। सोनम साहू ने कहा कि योजना की राशि से महिलाओं को अपने परिवार की जरूरतों में सहयोग करने के साथ त्योहारों की भी खुशी और उत्साह के साथ मनाने का अवसर मिल रहा है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए आर्थिक संबल का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।

बिलासपुर। रतनपुर रबदेव साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा श्री राधा माधव धाम में संत शिरोमणि विप्र कुल गौरव गोस्वामी तुलसीदास की जयंती एवं विष्णु स्मारक ग्रंथ पुनर प्रकाशन मंडल के सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा श्री राधा माधव व गोस्वामी तुलसीदास की पूजा अर्चना के साथ की गई इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत दिव्कांत जी महाराज रहे वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रबदेव साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष बलराम पांडे ने तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में किशन लाल तंबोली, के आर कौशिक, शंकर लाल पटेल, श्रीमती राजकुमारी बिसेन महिला मोर्चा भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर नीलम सिंह रही स्वागत भाषण होरीलाल गुप्ता ने दिया मुख्य अतिथि महोदय ने अपने उद्बोधन में



रामचरितमानस को आदर्श जीवन जीने का ग्रंथ बताया उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ में परिवार के सभी सदस्यों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य को बतलाया गया है इसके अनुरूप हम चलकर एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बलराम पांडे ने गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जन्म ही संघर्ष से शुरू हुआ जन्म के समय ही उनकी माता का निधन हो गया पिता ने उनका त्याग कर दिया दासी ने उनका पालन पोषण किया लेकिन उन्होंने भी उसे बाद में त्याग दिया इस प्रकार उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा और यही

संघर्ष की परिणति रामचरितमानस ग्रंथ की रचना के रूप में हुई द्वितीय सत्र में विष्णु स्मारक ग्रंथ के पुनर प्रकाशन मंडल के सदस्यों बलराम पांडे, राजेंद्र मिश्रा, राजेंद्र दुबे, विकल जायसवाल, भागीरथी सोनी, शिवानंद पांडे ,अनिल अग्रवाल, होरीलाल गुप्त, ज्ञान आधार शास्त्री, आनंद नगर कर, मुकेश जोशी, दिशश पांडे का सम्मान किया गया ज्ञात हो की सन् 1944 में श्री विष्णु महायज्ञ के पश्चात इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था जो बहुत कम लोगों के पास रहा गया था इसका पुनर प्रकाशन इन धर्म प्रेमियों के द्वारा किया गया।

नशे के सौदागरों पर बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई का त्वरित परिणाम, 3 आरोपियों को 15-15 साल की सजा

बिलासपुर। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना सिटी कोतवाली में दर्ज हथ्छ्क एक्ट के प्रकरण में माननीय विशेष ह्छ्क न्यायालय, बिलासपुर ने तीन आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खास बात यह है कि प्रकरण का विचारण लगभग 7 माह में पूरा हुआ। मामला अपराध क्रमांक 488/2025, धारा 21, 22 ह्छ्क एक्ट से संबंधित है। पुलिस ने 8 और 9 सितंबर 2025 को कार्रवाई करते हुए कुल 114 नग प्रत्येक 2 रू यांनी कुल 228 रू नशीली दवा बरामद की थी। इसके साथ ही प्रकरण में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक छत10/ब्रह्म2344, जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है, भी जब्त की गई थी। 8 सितंबर 2025 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने ज्वाली नाला के पास दबिश्वा दी। कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों के कब्जे से 62 नग ब्रह्मह्रदङुशहथ्छ्कदुडुडु ब्रुडुदुदुह्छ्कशुडु बरामद किए गए। इसके बाद 9 सितंबर को आरोपी दुर्गा वमां के कब्जे से 52 नग इंजेक्शन बरामद किए गए। इस तरह कुल 114 नग नशीले इंजेक्शन पुलिस के हाथ लगे। इस मामले में पुलिस ने प्रभावी और साक्ष्य-आधारित विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद विशेष ह्छ्क न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के निरंतर प्रयास..... !

■ वृक्षारोपण और जल संरक्षण से बढ़ रही हरियाली, बिलासपुर रेल क्षेत्र की हरित छटा बनी आकर्षण का केंद्र...



में लगातार कार्य किया जा रहा है। तीन वर्षों में 6 लाख से अधिक पौधों का रोपण- दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेलवे परिसरों, कॉलोनिनों एवं उपलब्ध खाली स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर हरित क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में 6 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। इन प्रयासों का सुंदर उदाहरण

बिलासपुर का रेलवे क्षेत्र है, जहां रेलवे कॉलोनिनों एवं विभिन्न रेल परिसरों में चारों ओर दिखाई देने वाली घनी हरियाली और वृक्षों की कतारें इस क्षेत्र को एक प्राकृतिक ‘ऑक्सीजन’ जैसा स्वरूप प्रदान करती हैं। यह हरियाली रेलवे परिसर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुखद वातावरण के निर्माण में भी

महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तालाबों के निर्माण एवं पुनर्विकास से जल संरक्षण को बढ़ावा- पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जल संसाधनों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्षाजल के संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेलवे परिसरों में नए तालाबों का निर्माण तथा पुराने तालाबों का पुनर्विकास एवं नवीनीकरण किया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में 17 नए तालाबों का निर्माण तथा 04 तालाबों का नवीनीकरण किया गया है। इन जल संरचनाओं के माध्यम से वर्षाजल का बेहतर संचयन, भू-जल स्तर को बनाए रखने तथा जल संसाधनों के संरक्षण में मदद मिल रही है।

हाईकोर्ट ने 56 नए सिविल जजों को दी पहली पोस्टिंग, 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पीएससी के जरिए चुने गए 56 नए सिविल जजों की पोस्टिंग, 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और अधिसूचनाओं के तहत हायर ज्यूडिशियल सर्विस और लोअर ज्यूडिशियल सर्विस के कई जजों के तबादले किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा प्रोबेशन पर नियुक्त 56 नए सिविल जजों (जूनियर डिजीजन) को पहली नव-नियुक्त अधिकारियों के 29 अगस्त तक अपनी नव-नियुक्त अधिकारियों के तहत हायर विशेष अदायत का विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।



निर्माण में तेजी, पेचवर्क और विद्युत व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश, महापौर ने नगर निगम के अधिकारियों की ली मीटिंग

मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष तौर पर ध्यान देने कहा

राजनांदगांव। नगर निगम के तकनीकी अधिकारियों की बैठक महापौर मधुसूदन यादव ने ली। इसमें उन्होंने निर्माण कार्य में प्रगति लाने तथा बाधिए एवं अगामी त्योहार व गणेश पर्व को देखते हुए शहर में पेचवर्क सहित विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के अलावा अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने निर्माण कार्यों की जानकारी लेकर कहा कि स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्य चालू कराए , चलते कार्य में गति लाकर समय-सीमा में पूर्ण कराए, उन्होंने योजना एवं निधि के कार्यों की जानकारी लेकर समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया। स्टेशन रोड एवं बीएसएनएल आफिस के पास शॉपिंग काम्पलेक्स निर्माण कार्य प्रक्रिया की जानकारी उपरांत कार्यारिेश देकर कार्य प्रारंभ कराने स्थल निरीक्षण कर बाधा हटा ले-आउट देने कहा. साथ ही निगम काम्पलेक्स जीर्णोद्धार तथा व्यवसायिक परिसर निर्माण के लिए की जा रही प्रक्रिया, बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति के संबंध में जानकारी लेकर आगे की प्रक्रिया के लिए चर्चा



कर दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि रोड, नाली निर्माण के अलावा चल रहे अन्य निर्माण कार्य में समय सीमा का ध्यान रखकर कार्य में गति लाए, किसी प्रकार की परेशानी पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही. पानी निकासी पर ध्यान देने कहा गया महापौर श्री यादव ने कहा कि बारिश को देखते हुए पानी भरान क्षेत्रों में पानी निकासी का विशेष ध्यान रखा जाए, त्योहार एवं

आगामी गणेश पर्व को देखते हुए सड़कों में पेचवर्क कर मरम्मत करे, बारिश में सुगम आवागमन के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करे, साथ ही शहर में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि खम्बा लाइट बंद होने की शिकायत का प्रथमिकता से निराकरण करे।बारिश एवं त्योहार के मददे विद्युत मरम्मत समग्री का पर्याप्त

भण्डारण रखे. आयुक्त जीआर मरकाम ने कहा कि निर्माण कार्यों के साथ साथ पेयजल, विद्युत व्यवस्था के अलावा सामुदायिक शौचालय का भी निरीक्षण करे. शौचालयों में दरवाजा टूटने तथा अन्य परेशानी संबंधित शिकायते प्राप्त होती है, जिसके निराकरण के लिए संचालक को समझाइश देकर व्यवस्था दुरुस्त कराए, निर्माण कार्यों की मानिट्रिंग कर प्रगति से अवगत कराए.

स्मार्ट मीटर हटाओ, पुराना मीटर लगाओ अभियान को लेकर कांग्रेस का बैठक संपन्न

बलौदा बाजार के वार्ड 15 में घर-घर पहुंचकर भराए गए फॉर्म



बलौदाबाजार। «स्मार्ट मीटर हटाओ, पुराना मीटर लगाओ» अभियान को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय, बलौदाबाजार में महत्वपूर्ण ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान के जिला प्रभारी सकलेन कामदार एवं जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सुमित्रा धृतलहरे जी विशेष रूप से उपस्थित रही।बैठक का आयोजन शहर कांग्रेस कमेटी बलौदाबाजार के अध्यक्ष प्रवीण सेन के नेतृत्व में किया गया। बैठक में अभियान को शहर के प्रत्येक वार्ड एवं बृथ स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाने तथा अधिक से अधिक नागरिकों को अभियान से जोड़ने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक के पश्चात अभियान के जिला प्रभारी सकलेन कामदार, जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सुमित्रा धृतलहरे जी एवं शहर कांग्रेस कमेटी के

अध्यक्ष प्रवीण सेन सहित कांग्रेसजनों ने वार्ड क्रमांक 15 में पहुंचकर आम नागरिकों से संपर्क किया। इस दौरान स्मार्ट मीटर से संबंधित जानकारी देते हुए नागरिकों के फॉर्म भरवाए गए तथा उनकी समस्याओं एवं चिंताओं को भी सुना गया।जिला प्रभारी सकलेन कामदार ने कहा कि अभियान को केवल बैठक तक सीमित न रखते हुए प्रत्येक वार्ड में घर-घर तक पहुंचाया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ता आम उपभोक्ताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को समझेंगे और अभियान के फॉर्म भरवाने में सहयोग करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी की

अध्यक्ष सुमित्रा धृतलहरे ने कहा कि जनहित से जुड़े इस अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतर्ें और आम जनता की आवाज को मजबूती से उठाए।हर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सेन ने कहा कि शहर के सभी 21 वार्डों में अभियान को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर नागरिकों से संपर्क करेंगे तथा स्मार्ट मीटर के संबंध में उनके फॉर्म भरवाने एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे।

सड़क बना डावरी शुध लेने वाला कोई नहीं



बलौदा बाजार। वर्षों से नवीनीकरण का बात जोह रहे खस्ताहाल सड़क में इन दिनों डावरी नुमा गुड्डा बन गया है। इस गुड्डे में आए दिन दो पहिया एवं साइकिल चालक पस कर परेशान हो रहे हैं एवं स्कूल बस व एंबुलेंस इसी मार्ग से होकर बलौदा बाजार आते हैं किंतु इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। विदित हो को बलौदा बाजार विधानसभा के

विधायक एवं प्रदेश के राजस्व मंत्री के गृह ग्राम चापा जाने का रास्ता यहीं से होकर जाता है। साथ ही इस क्षेत्र के कुछ छुट भैये नेता भी इसी मार्ग से होकर शहर में आकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। किन्तु विडंबना देखिए करीब तीन माह हो गया सड़क के गुड्डे में पानी भर जाने से कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। दुर्घटना को लेकर किसी

भी जिम्मेदार नेता या राजनेता हो या अधिकारी इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। इस मार्ग में आवागमन करने वाले आम जनता काफी परेशान है क्योंकि कई बार विभाग से गुहार लगाने के बाद भी मांग को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। जबकि सुहेला हथबंद जाने का यह मुख्य मार्ग है फिर भी ग्राम कोकड़ी में स्थिति जस की तस बनी हुई है।

मैनेजर ने किया 11 लाख रुपए का ग़बन, मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

मामला कोतवाली एरिया का, जाँच के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

राजनांदगांव। अरूण एग्रीकल्चर में मैनेजर के पद पर कार्यरत व्यक्ति पर किसानों को बेचे गए ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों की बिक्री राशि में लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगा है। मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी कुमुद उपाध्याय (52 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, प्रार्थी ने बीते 17 अगस्त को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी कुमुद उपाध्याय, जो इंदिरा नगर स्थित वृंदावन कॉलोनी का निवासी है, अरूण एग्रीकल्चर में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। आरोप है कि 1 अप्रैल 2025 से 7 अप्रैल 2026 के बीच फर्म के ट्रैक्टर एवं कृषि



उपकरण किसानों को कुल 14 लाख 61 हजार रुपए में बेचे गए. लेकिन बिक्री की पूरी रकम फर्म में जमा नहीं की गई। पुलिस की पूछताछ और जांच के दौरान आरोपी द्वारा राशि के गबन की बात स्वीकार की. आरोपी ने 3 लाख 3 हजार रुपया वापस किए. जबकि 11 लाख 7 हजार रुपये फर्म में जमा नहीं करने की बात बताई गई। मामले में कोतवाली

थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 443/26, धारा 316(4), 336(3), 344(1) बीएसएस के तहत अपराध दर्ज किया।

खाता-बही जल, आरोपी जेल भेजा गया

पुलिस ने आरोपी को थाना तलब कर पूछताछ की। उसके कब्जे से खाता-बही जन्म की गई। जांच में पर्याप्त अपराध साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने 19 अगस्त 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

परिक्षेत्रीय साहू संघ झीट में सामाजिक नियमावली कार्यशाला एवं इकाई पदाधिकारियों का सम्मान संपन्न

पाटन अम्लेश्वर। तहसील साहू संघ पाटन अंतर्गत परिक्षेत्रीय साहू संघ झीट की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक एवं सामाजिक नियमावली कार्यशाला का आयोजन परिक्षेत्रीय साहू भवन में किया गया। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी, इकाई पदाधिकारी, वरिष्ठजन एवं सामाजिक सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रदेश साहू समाज की सामाजिक नियमावली की जानकारी प्रदान करने के साथ ही समाज में एकता, अनुशासन, आपसी समन्वय एवं सामाजिक दायित्वों को मजबूत करना रहा। साथ ही सभी लोगों को सामाजिक नियमावली का बुक भी प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के दौरान इकाई पदाधिकारियों एवं इकाई अध्यक्षों को निरुक्ति पत्र एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही समाज के प्रति उनके योगदान एवं जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। बैठक में सामाजिक हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा आवश्यक निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने समाज की एकता एवं संगठन को मजबूत बनाने तथा सामाजिक नियमावली का पालन सुनिश्चित करने में पूर्ण



सहयोग देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में परिक्षेत्रीय अध्यक्ष गायत्री साहू, उपाध्यक्ष सुखदेव साहू एवं मधुकांता साहू, संगठन सचिव ओमप्रकाश साहू एवं मती हेमलता साहू, सचिव टीकाराम साहू, कोषाध्यक्ष राधे साहू, संरक्षक मोहन साहू, तहसील प्रतिनिधि रामाधार साहू (एलडमैन), युवा प्रकोष्ठ राजू साहू, प्रचार सचिव भारत कुमार साहू, मीडिया प्रभारी भूपेश साहू, जनपद सदस्य दामिनी राकेश साहू, मती योगिता साहू सहित समाज के वरिष्ठजन एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। वरिष्ठजनों में



साहू, प्रहलाद साहू, रामु राम साहू, अन्नपूर्णा साहू, मती सरस्वती साहू, देवकी साहू, अमरीका साहू, संतोषी साहू, लक्ष्मी साहू, पद्मिनी साहू, पुण्या साहू, सुनीता साहू, मुनेश्वर साहू, उत्तम साहू सहित बड़ी संख्या में समाज के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में परिक्षेत्रीय साहू संघ झीट द्वारा समाज की एकता, संगठनात्मक मजबूती एवं सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया गया। आयोजन को सफल बनाने में सभी पदाधिकारियों एवं समाजजनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।



तीजुराम साहू, प्रद्युम्न साहू, कल्याण साहू, शिव कुमार साहू, तुलाराम साहू, सुखचंद साहू, टिकेश्वर साहू, ध्रुव साहू, यशवंत साहू, बरसाती साहू, ओम प्रकाश साहू, हिलेश्वर साहू, लाला राम साहू, रोशन साहू, मुरारी साहू, देव नारायण साहू, तीरथ साहू, देवेंद्र साहू, पीलाराम साहू, मोहन

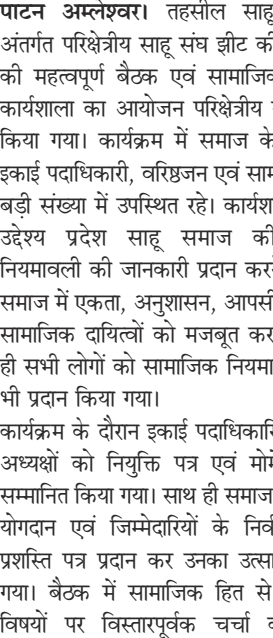
अस्वास्थ्यकर दशा में भंडारित 10 किलोग्राम बूंदी किया गया नष्ट खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई

बलौदाबाजार। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा बुधवार को पलारी क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान एक हॉटल में अस्वच्छ स्थिति में भण्डारित 10 किलो बूंदी को नष्ट कराया गया एवं नोटिस जारी किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार माँ आशापुरी बीकानेर स्वीट्स पलारी, बब्बू हॉटल पलारी, एसके सुपर मार्ट पलारी, प्रकाश ढाबा एंड फैमली रेस्टोरेंट मेन रोड कुकदा (पलारी) का निरीक्षण कर मिल्क केक, नमकीन, पनीर, वेज बिरयानी एवं खजूर का नमूना लेकर जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला प्रेषित किया गया। बब्बू हॉटल पलारी में अस्वास्थ्यकर दशाओं में भंडारित 10 किलोग्राम बूंदी को मौके पर नष्ट कराया गया। प्रकाश ढाबा एंड फैमली रेस्टोरेंट मेन रोड कुकदा (पलारी) में अस्वच्छता पाए जाने पर मौके पर नोटिस जारी किया गया। खाद्य रव औषधी प्रशासन विभाग ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे त्योहारों के दौरान केवल उच्च गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों का निर्माण व विक्रय करें।

बिना खाद्य पंजीयन या लाइसेंस के संचालित होने वाले अस्थायी स्टॉलों और शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण हाट-बाजारों की ओर होने वाली सदिध मिठाइयों की सप्लाई चैन पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

विभाग ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे जागरूक रहें और पैकेटबंद मिठाइयों या सामग्रियों को खरीदते समय लेबलिंग की जाँच रव बिल अवश्य लें। ज्ञातव्य है कि रक्षाबंधन पर्व एवं बरसात के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों को सुरक्षित, शुद्ध,

गुणवत्तापूर्ण एवं मानक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में सात दिवसीय सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान ँबने बाबो-बने रहिवो «अभियान संचालित किया जा रहा है।



आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिले की उपलब्धि

जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वास्थ्य मंत्री के हाथों मिला प्रशस्ति पत्र

बलौदाबाजार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी रूप से लागू करने तथा स्वास्थ्य संबंधी डिजिटल रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार को राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली संस्था के रूप में प्रशस्ति पत्र लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदान किया । यह सम्मान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्टेट मॉडल डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटीज,राज्य स्तरीय उद्घाटन कार्यशाला में प्रदान किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं संजीव कुमार झा तथा संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत

सरकार विक्रम पगारिया उपस्थित रहे।कार्यशाला का आयोजन 19 अगस्त 2026 को रायपुर में किया गया जिसमें राज्य स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन एवं डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। जिला

चिकित्सालय बलौदा बाजार द्वारा एबीडीएम एवं हेल्थ रिकार्ड लिंकेज के क्षेत्र में किए गए प्रभावी कार्य को राज्य स्तर पर सराहा गया। अस्पताल में डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल माध्यम से लिंक करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल

प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप यह उपलब्धि हासिल हुई है।कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने इस उपलब्धि पर जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य टीम को बधाई देते हुए कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से नागरिकों को एक डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश अवस्थी ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पहल है, जिसका उद्देश्य देश में एक मजबूत, सुरक्षित और आपस में जुड़े हुए डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र का निर्माण करना है।इसके माध्यम से मरीजों के

स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के बेहतर आदान-प्रदान की दिशा में कार्य किया जा रहा है।इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के माध्यम से नागरिकों को एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान उपलब्ध होती है। इससे मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से व्यवस्थित एवं आवश्यकता के अनुसार साझा कर सकते हैं। साथ ही, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के माध्यम से मरीज की पूर्व स्वास्थ्य जानकारी चिकित्सकों तक उपलब्ध होने से उपचार एवं फॉलोअप को अधिक सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलती है ।



मारगांव व दीवानभेड़ी में खुलेगी राशन दुकान, संचालन हेतु 27 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

डोंगरगांव नगर। अनुभाग डोंगरगांव के विकासखंड डोंगरगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत मारगांव एवं ग्राम पंचायत दीवानभेड़ी में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान खुलने जा रही है। नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु 27 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित की गई है। प्रशासन द्वारा आधिकारिक जानकारी मुताबिक नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु इच्छुक एवं पात्र जिले में स्थित वृहत्तकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समिति (लेम्पस), प्राथमिक कृषि शाख समिति, वन सुरक्षा समिति, महिला स्वसहायता समूह, अन्य उपभोक्ता सहकारी समिति निर्धारित तिथि तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ विहित प्रारूप एक में आवेदन पत्र कार्यालय



अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगांव में प्रस्तुत कर सकते हैं। मीडिया को प्रदाय जानकारी के मुताबिक प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (निचयंत्र) आदेश 2016 के तहत

दुर्ग में नवीन न्यायालय भवन का भूमिपूजन, डिजिटल न्यायिक सेवाओं का भी शुभारंभ

मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने रखी आधारशिला, 'संधि सेतु' पुस्तक का किया विमोचन



दुर्ग। जिला दुर्ग की न्यायिक व्यवस्था के लिए शनिवार का दिन महत्वपूर्ण रहा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने नवीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के निर्माण के लिए भूमिपूजन एवं फण्डेशन स्टोन लेटिंग सेरेमनी की। इस अवसर पर न्यायिक अधोसंरचना के सुदृढीकरण के साथ डिजिटल न्यायिक सेवाओं और सामुदायिक मध्यस्थता से जुड़ी विभिन्न पहलों का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधिपति के साथ न्यायाधिपति श्री पी.पी. साहू, श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी, श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री विष्णु दत्त

गुरु एवं श्री अमिर्तेन्द्र किशोर प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग श्री के. विनोद कुजूर के स्वागत उद्बोधन से हुआ। उन्होंने नवीन न्यायालय भवन की आवश्यकता और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक न्यायिक परिसर के विकास पर प्रकाश डाला। इसके बाद मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने विधिवत भूमिपूजन कर नवीन भवन की आधारशिला रखी। प्रस्तावित भवन से न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और न्यायाधीशों को बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं

उपलब्ध होने की उम्मीद है। 'संधि सेतु' पुस्तक का विमोचन- कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता के विषय पर तैयार पुस्तक 'संधि सेतु' का मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने विमोचन किया। पुस्तक का उद्देश्य संवाद, सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर विवादों के समाधान की अवधारणा को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से विवाद-मुक्त एवं सौहार्दपूर्ण समाज की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी दस्तावेजीकृत किया गया है। डिजिटल न्याय को मिला नया आयाम-

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सूचना प्रौद्योगिकी टीम द्वारा विकसित विभिन्न डिजिटल न्यायिक पहलों का शुभारंभ एवं वीडियो प्रस्तुतीकरण किया गया। इनमें केशलेस फ़इन पेमेंट सुविधा, स्क्रम मोबाइल एप्लीकेशन (ट्रसटहबइस) और कोर्ट फ़ीस टिकट जनरेशन सिस्टम प्रमुख रहे। इन पहलों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाना तथा नागरिकों एवं न्यायिक हितधारकों को न्यायालयीन सेवाएं अधिक आसानी से उपलब्ध कराना है। न्याय को सरल और जनसुलभ बनाने पर जोर- मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने अपने

उद्बोधन में आधुनिक न्यायिक अधोसंरचना, तकनीकी नवाचार और जन-केंद्रित न्याय व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था की सफ़रता तभी है, जब न्याय अधिक सुलभ, सरल, पारदर्शी और आमजन के निकट हो। उन्होंने डिजिटल न्यायिक सेवाओं और सामुदायिक मध्यस्थता जैसी पहलों की सराहना की। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी, जिला न्यायपालिका के अधिकारी-कर्मचारी, अधिवक्ता, विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पैरालीगल वॉलंटियर्स, सामाजिक प्रतिनिधि तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के

प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अंत में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग श्रीमती सुमन एक्का ने आभार व्यक्त किया। जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग ने भी मुख्य न्यायाधिपति का आभार व्यक्त किया। दुर्ग से चयनित दस बार कार्डिनल के सदस्यों ने भी मुख्य न्यायाधिपति का अभिनंदन किया। नवीन न्यायालय भवन का भूमिपूजन, 'संधि सेतु' पुस्तक का विमोचन और डिजिटल न्यायिक पहलों का शुभारंभ दुर्ग की न्याय व्यवस्था को आधुनिक, सुलभ, तकनीक-सक्षम और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई, दूषित दशा मे रखे 92 किलो चमचम कराया गया नष्ट



बेमेतरा। जिले मे 7 दिवसीय सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान बने खाबो-बने रहिबो 2.0 संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी मे निरीक्षण के दौरान एक होटल मे अस्वच्छ और दूषित दशाओं में चमचम मिठाई तैयार किया जा रहा था,मौके पर मौजूद लगभग 92 किलोग्राम चमचम मिठाई को तत्काल ज्वब कर नष्ट कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरु नानक वाड्ड, भाटापारा में नीरज कुमार मूल निवासी रोरांगपुर, जिला औरैया उतर प्रदेश द्वारा खुले में, बेहद अमअस्वच्छ माहौल में जहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही थीं चमचम मिठाई का निर्माण किया जा रहा था।

जब टीम ने संचालक से खाद्य लाइसेंस या पंजीजन संबंधी दस्तावेज मागे, तो वह कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत करने में पूरी तरह असमर्थ रहा। अस्वच्छ और दूषित दशाओं में मिठाई तैयार किए जाने के कारण खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मौके पर ही चमचम के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। इसके साथ ही जनमस्वास्थ्य को होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए मौके पर मौजूद लगभग 92 किलोग्राम चमचम मिठाई को तत्काल ज्वब किया गया और नष्टीकरण की कार्रवाई हेतु नगर निगम की गाड़ी को सौंप दिया गया।

अल्ट्राटेक रावन सीएसआर द्वारा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सम्मान समारोह कार्यक्रम



बलौदाबाजार। अल्ट्राटेक रावन सीएसआर द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यक्रम के 60 वर्ष से अधिक 120 वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रशासनिक प्रमुख सजीव मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि वरिष्ठ नागरिक परिवार और समाज के मार्गदर्शक होते हैं। उनके अनुभव और जीवन से प्राप्त सीख युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर

भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान स्वरूप उपहार प्रदान किए गए तथा उनके आवश्यकताओं और समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सेक्युरिटी डीपार्टमेंट प्रमुख राजू सिंग एवं सीएसआर प्रमुख निरुपा श्रीवास्तव की उपस्थिति रही एवं कार्यक्रम को सफल बनाने में सीएसआर अधिकारी ज्योत्सना पति एवं रंजय पाण्डेय तथा टीम से जानकी यादव, हेमलता ध्रुव, सुरेन्द्र यादव, ताराचंद वर्मा, सुनिता निषाद, साहित्य बोधे एवं गुमान साहू की भूमिका रही।

सावन में गूँजा हर-हर महादेव, अग्रवाल समाज ने कराया भव्य रुद्राभिषेक



12 पार्थिव ज्योतिर्लिंगों का विधिवत अभिषेक, 40-50 जोड़ों ने लिया हिस्सा

दुर्ग। सावन मास के पावन अवसर पर अग्रवाल समाज, दुर्ग की ओर से अग्रसेन भवन में भव्य रुद्राभिषेक एवं 12 पार्थिव ज्योतिर्लिंग अभिषेक का आयोजन किया गया। धार्मिक अनुष्ठान

में अग्रवाल महिला मंडल और अग्रवाल युवा मित्र मंडल सहित समाज के बड़ी संख्या में सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। सुबह से ही अग्रसेन भवन में मंत्रोच्चारण और भगवान भोलेनाथ के जयकारों से भक्तिमय वातावरण बना रहा। कार्यक्रम में करीब 40 से 50 जोड़ों ने शामिल होकर विधि-विधान से भगवान शिव का अभिषेक एवं



पूजा-अर्चना की। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष ललित सेक्सरिया ने बताया कि समाज की ओर से पिछले करीब 10 वर्षों से लगातार रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। कभी पूरे सावन मास तो कभी विशेष तिथियों पर यह धार्मिक आयोजन कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी सावन मास में 12 पार्थिव ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक कर समाज की सुख-

समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि आयोजन का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और देश में सुख, शांति, समृद्धि एवं आपसी सद्भाव की कामना करना भी है। कार्यक्रम के दौरान भगवान भोलेनाथ से सभी के जीवन में सुख-शांति और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई।

लोहिया पेपर मिल हादसा पीड़ित परिवार को मिला 25.51 लाख का मुआवजा

बेमेतरा। लोहिया पेपर मिल में हुए दुःखद हादसे के शिकार पीड़ित परिवार के अधिकारों के लिए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने एकजुट होकर आवाज उठाई। संगठन के निरंतर संघर्ष और प्रयासों के फलस्वरूप पीड़ित परिवार को न्याय एवं उचित आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। क्रांति सेना के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पीड़ित परिवार को कुल 25,51,000 (पच्चीस लाख एकवन हजार रुपये) की सहायता राशि का भुगतान किया गया। इसमें शामिल हैं: 20,00,000 (बीस लाख रुपये) का चेक, 5,00,000 (पांच लाख रुपये) की बीमा राशि, 51,000 (इक्कवन हजार रुपये) काठी-माटी (अंतिम संस्कार/आपत) सहायता राशि। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रतिनिधियों ने कहा, यह जीत छत्तीसगढ़िया समाज की एकजुटता और संघर्ष का परिणाम है। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा मुस्तेदी से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इस दौरान प्रमुख रूप से सूर्या



चौहान (शहर अध्यक्ष, जेसीपी), निलेश साहू (जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना), खेमू साहू (शहर उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़िया युवा क्रांति सेना), पुरेंद्र साहू (जिला अध्यक्ष), गजेंद्र निषाद (जिला उपाध्यक्ष), मोहन परगनिया (खंड अध्यक्ष), नंदू छत्तीसगढ़िया जिला मीडिया प्रभारी, के साथ गोपु, शिव, योगेश, प्रदीप, ललित, ओंकार, कुबेर, हरेंद्र एवं अन्य सहयोगी पदाधिकारी व सेनानी मौजूद रहे।

छात्रावासों की बदहाल व्यवस्था पर बैठक में सफाई भोजन से गुटबाजी तक

कवर्धा। जिले में संचालित आश्रम एवं छात्रावासों की व्यवस्था को लेकर 18 अगस्त को आयोजित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में कई गंभीर मुद्दे सामने आए। बैठक में जिला पंचायत शिक्षा समिति के अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री के जिला प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, विधायक प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी, प्राचार्य शासकीय कन्या शिक्षा परिसर भोरमदेव, प्राचार्य स्वामी करपात्री जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कवर्धा, सहायक संचालक/क्षेत्र संयोजक/ सहायक लेखा अधिकारी आदिवासी विकास, छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य जिले में संचालित आश्रम एवं छात्रावासों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करना था, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी है कि समीक्षा के बावजूद व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हैं।



जिले के कई छात्रावासों और आश्रमों में सफाई व्यवस्था बदहाल होने की बात सामने आ रही है। जहां 50 से लेकर 300 से अधिक छात्र-छात्राएं निवास करते हैं, वहां नियमित सफाई व्यवस्था के लिए पर्याप्त स्वीपर तक उपलब्ध नहीं हैं। जानकारी के अनुसार कुछ संस्थाओं में सप्ताह में केवल एक दिन स्वीपर पहुंचता है। ऐसे में बड़ी संख्या में बच्चों के रहने वाले परिसरों की नियमित सफाई-सफाई किस तरह होती होगी, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के

लिए भोजन व्यवस्था भी सवाल के घेरे में है। बच्चों को निर्धारित मीनू के अनुसार पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर भोजन की थाली से ही मीनू गायब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। बैठक में भोजन के मीनू को लेकर चर्चा के दौरान सोया बड़ी का मुद्दा भी उलझन का कारण बना। सवाल यह है कि जब बच्चों के भोजन की गुणवत्ता और निर्धारित मीनू पर ही स्पष्टता नहीं बन पा रही है तो फिर सरकारी व्यवस्था की निगरानी किस स्तर पर हो रही है। बैठक में पढ़ाई-लिखाई, बच्चों के स्वास्थ्य, भोजन, सफाई-सफाई, भवनों की स्थिति, मूलभूत सुविधाओं और छात्रावास संचालन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। खास तौर पर भवनों की स्थिति और परिसरों की नियमित सफाई-सफाई किस तरह की वास्तविकता पर गंभीरता से निगरानी की जरूरत महसूस होती है। सबसे चिंताजनक

स्थिति यह रही कि बच्चों की बुनियादी सुविधाओं और छात्रावासों की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से आगे बढ़कर बैठक में पंडरिया विधानसभा और कवर्धा विधानसभा से जुड़े विषय भी चर्चा में आने लगे। बैठक के दौरान गुटबाजी से जुड़े स्वर सामने आना एकता का संकेत नहीं, बल्कि ऐसे संस्थान हैं जहां दूरदराज और जरूरतमंद परिवारों के बच्चे रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनके भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता से किसी भी तरह का समझौता सीधे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। ऐसे में निगरानी समिति की बैठक केवल कागजी समीक्षा तक सीमित न रहकर ग्राहल पर औचक निरीक्षण, नियमित सफाई, पर्याप्त स्वीपर, मीनू के अनुसार भोजन और भवनों की वास्तविक स्थिति की जांच सुनिश्चित करे।

रक्षाबंधन पर सजा राखियों का बाजार, भाई-बहन के प्रेम का पर्व मनाने को तैयार



दुर्ग/भिलाई। भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व नजदीक आते ही दुर्ग-भिलाई के बाजार रंग-बिरंगी राखियों से सजकर तैयार हो गए हैं। शहर के प्रमुख बाजारों, दुकानों और अस्थायी राखी स्टॉलों पर राखियों की आकर्षक श्रृंखला लोगों का ध्यान खींच रही है। बहनें अपने भाइयों की पसंद के अनुसार राखियां खरीदने बाजार पहुंच रही हैं, वहीं दुकानदारों ने भी इस बार नए डिजाइन और आकर्षक वैरायटी से ग्राहकों को लुभाने की पूरी तैयारी की है। राखी बाजार में इस बार पारंपरिक राखियों के साथ आधुनिक डिजाइन की राखियों की भी खूब मांग देखने को

मिल रही है। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, सुपरहीरो, मोटिफ और रंग-बिरंगी फैसी राखियां उपलब्ध हैं। वहीं युवाओं के लिए स्टाइलिश, ब्रेसलेट और आकर्षक डिजाइन वाली राखियां पसंद की जा रही हैं। महिलाओं और युवतियों के बीच मोती, कुंदन, स्टोन वर्क, रुद्राक्ष और पारंपरिक कलात्मक डिजाइन वाली राखियों की मांग बनी हुई है। बाजार में हर बजट की राखियां उपलब्ध- दुर्ग-भिलाई के बाजारों में सामान्य से लेकर प्रीमियम श्रेणी तक की राखियां उपलब्ध हैं। कम कीमत वाली साधारण राखियों से लेकर डिजाइनर और विशेष रूप से तैयार की गई महंगी



राखियों तक दुकानदारों ने बड़ी रेंज राखी है। इससे हर वर्ग के ग्राहक अपनी सुविधा और बजट के अनुसार राखी खरीद सकते हैं। भाई की पसंद का भी रखा जा रहा ध्यान- बाजार में भाइयों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई तरह की राखियां उपलब्ध कराई गई हैं। धार्मिक प्रतीकों, ओम, स्वास्तिक, रुद्राक्ष और भगवान शिव से जुड़ी राखियों के साथ-साथ युवाओं के लिए सिंपल और ट्रेंडी डिजाइन भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए आकर्षक पैकिंग और रंगीन राखियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।

राखी के साथ गिफ्ट पैक की भी मांग- रक्षाबंधन को लेकर राखी के साथ उपहार देने का चलन भी बढ़ा है। बाजार में राखी के साथ रोल-चावल की छोटी थाली, मिठाई और गिफ्ट पैक के विकल्प भी उपलब्ध हैं। कई दुकानों पर आकर्षक पैकिंग के साथ तैयार राखी कॉम्बो ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं। बहनें राखी के साथ भाई की पसंद की मिठाई और उपहार भी खरीद रही हैं। दुकानदारों को कारोबार बढ़ने की उम्मीद- रक्षाबंधन को लेकर बाजार में बढ़ी चहल-पहल से दुकानदारों में भी उत्साह है। राखी विक्रेताओं का कहना है कि पर्व के करीब



आते ही ग्राहकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। शहर के प्रमुख बाजारों में राखी की दुकानें और स्टॉल सज गए हैं। शाम के समय बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ने से पर्व का उत्साह साफ नजर आ रहा है। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी को मजबूत करने का अवसर भी है। यही वजह है कि इस पर्व को लेकर हर उम्र के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार की रौनक और राखियों की रंगीन दुनिया ने दुर्ग-भिलाई में रक्षाबंधन के आगमन का एहसास कराना शुरू कर दिया है।